▸▸ वर्ष : 35 ▸▸ अंक : 40 ▸▸ मुंबई, गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 ▸▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸ मूल्य : 3 रुपए ▸▸ epaper.dobajedopahar.com ▸▸ संपादक : अरुण लाल ▸▸ संरक्षक : एन. के. पुरोहित

बारामती-राहुरी उपचुनाव आज

महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 23 अप्रैल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की दो हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों—बारामती और राहुरी—पर उपचुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। 21 अप्रैल की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब सभी की निगाहें आज होने वाली वोटिंग पर टिकी हैं। बारामती में महायुति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जहाँ अंतिम दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुप्रिया सुले जैसे दिग्गजों ने रैलियों में हिस्सा लिया। वहीं, अहिल्यानगर जिले की राहुरी सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहाँ भाजपा और शरद पवार गुट के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है।

चुनावी समीकरण और प्रमुख उम्मीदवार

बारामती सीट पर सहानुभूति फैक्टर की लहर है, जहाँ अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार महायुति की मुख्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस द्वारा अपना प्रत्याशी वापस लेने के बावजूद, 23 निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी के कारण यहाँ चुनाव निर्विरोध नहीं हो सका है। दूसरी ओर, राहुरी विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है; यहाँ भाजपा के अक्षय कर्डिले का सामना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के गोविंद मोकाटे से है।

DBD
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

आज होगी अग्निपरीक्षा

बंगाल और तमिलनाडु में मतदान आज

एजेंसी । नई दिल्ली

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए गुरुवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में मतदान कर शामिल होने की अपील की है। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 16 जिलों की 152 सीटों के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार, मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक जारी रहेगा। दोनों राज्यों में मंगलवार से पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी हैं। तमिलनाडु में 5.73 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बंगाल में पहले चरण के लिए 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। दस से अधिक देशों के प्रतिनिधि दोनों राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को नजदीक से देखेंगे।

प. बंगाल विधानसभा : पहले फेज की वोटिंग आज

एजेंसी । कोलकाता

23 अप्रैल को होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण अब एक बेहद अहम मुकाबले में बदल गया है। इस चरण में धुआंधार प्रचार, चुनावी वादों, पहचान की राजनीति और कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के अभूतपूर्व इंतजाम नजर आए हैं। इस दौर में मुख्य लड़ाई सिर्फ़ विधानसभा सीटों के लिए नहीं, बल्कि अलग-अलग नैरेटिव के बीच है, जिसमें मतदाता यह तय करेंगे कि वे ममता बनर्जी के लोक-कल्याण मॉडल को जारी रखना चाहते हैं, या फिर बीजेपी की अगुवाई वाले उस बदलाव को चुनना चाहते हैं, जिसे प्रशासनिक सुधार, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), घुसपैठ-विरोधी ऐलान और रोज़गार सृजन के वादों से सजाया गया है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा और प्रबंधन को देखते हुए चुनाव को सिर्फ दो चरणों में समेट दिया है।

पहले चरण में कितनी सीटों पर है मतदान?

कल पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर मतदान होगा। यह चुनाव का सबसे बड़ा चरण है क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा सीटों का फैसला जनता के हाथ में होगा। पहले चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं लगभग 44,376 बूथों पर वोटिंग होगी।

किन जिलों में पड़ेंगे वोट?

पहले चरण के मतदान में मुख्य रूप से उत्तर बंगाल और कुछ अन्य जिलों को शामिल किया गया है। इनमें कूचबिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। साथ ही नदिया, मुर्शिदाबाद और हुगली के कुछ हिस्सों में भी कल ही वोट डाले जाएंगे।

तमिलनाडु : एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान

राज्य में इस बार 5.67 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनावी नतीजे तय करेंगे, जिनमें 14.5 लाख नए वोटर शामिल हैं और महिलाओं की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है। वोटिंग के लिए 75 हजार से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और 3 लाख कर्मचारी तैनात किए गए हैं।। वहीं मतदान से पहले ही हजारों करोड़ की नकदी और सामान की जब्ती ने साफ संकेत दिया है कि प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर बेहद सतर्क है। अब 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर सबकी नजर टिकी है, जहां करोड़ों मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

5 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे फैसला

इस चुनाव में 5.67 करोड़ से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। करीब 2.89 करोड़ महिला वोटर और 2.77 करोड़ पुरुष वोटर हैं। इससे साफ है कि इस बार महिलाओं की भूमिका चुनावी नतीजों में अहम हो सकती है। वहीं 14.5 लाख से ज्यादा नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे।

बूथ से लेकर मशीन तक पूरी तैयारी

राज्य भर में 75 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो 33 हजार से अधिक केंद्रों पर फैले हैं। इन पर करीब 3 लाख कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वोटिंग के लिए 1 लाख से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लगाई गई हैं, साथ ही अतिरिक्त मशीनें भी रिजर्व में रखी गई हैं ताकि किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न हो।

मालेगांव बम धमाका

चारों आरोपी बाइज्जत बरी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई/मालेगांव

साल 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार चारों आरोपियों, लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, जिसके आधार पर उन्हें निर्दोष माना गया। मालेगांव में हुए इन सीरियल धमाकों में 37 लोगो की जान चली गयी थी। बता दें कि यह मामला 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए सीरियल ब्लास्ट से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस दिन शब-ए-बारात के मौके पर तीन प्रमुख जगहों, बड़ा कब्रिस्तान, हमीदिया मस्जिद और मुशावरत चौक पर धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में करीब 37 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के तुरंत बाद जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। ATS ने अपनी शुरुआती जांच में इस हमले के तार प्रतिबंधित संगठन सिमी से जोड़ते हुए 9 मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2006 से 2011 के बीच ATS लगातार इसे इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा मामला बताती रही और 2011 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच में ATS की थ्योरी पर मुहर लगा दी।

मस्जिद के पास धमाके में 37 लोगों की हुई थी मौत

स्वामी असीमानंद के बयान ने केस में छेड़ी थी नई बहस

मामले में बड़ा मोड़ 2010 में तब आया, जब स्वामी असीमानंद के बयान ने नई बहस छेड़ दी। उन्होंने 2006 से 2008 के बीच मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस धमाकों में हिंदू संगठनों की संलिप्तता का दावा किया। हालांकि, ATS पहले ही इस एंगल को खारिज कर चुकी थी। इसके बाद 2011 में NIA ने जांच अपने हाथ में ली और केस की दिशा बदल गई। NIA ने 2013 में 4 नए आरोपियों, लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को गिरफ्तार किया और ATS व CBI की जांच को खारिज करते हुए कहा कि पहले गिरफ्तार किए गए 9 मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

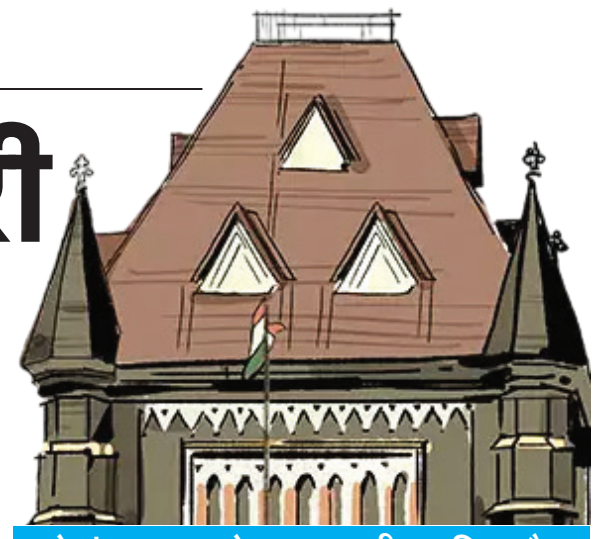

मालेगांव बम धमाके का असली मुजरिम कौन?

बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले ने 2006 के मालेगांव धमाका मामले को अजीब स्थिति में डाल दिया है कि आखिर इस मामले का असली मुजरिम कौन है? क्योंकि कोर्ट ने पहले ही मूल आरोपियों को बरी कर दिया था और अब हाईकोर्ट ने भी उनकी जगह लाए गए आरोपियों पर से भी आरोप रद्द कर दिए।

2021 में सभी 9 मुस्लिम आरोपी कर दिए गए थे बरी

NIA के इसी बयान के आधार पर 2021 में उन सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस दौरान यह भी सामने आया कि ATS और NIA की चार्जशीट और जांच में काफी अंतर था, जहां ATS ने इसे इस्लामिक आतंकवाद बताया, वहीं NIA ने हिंदूवादी अतिवादियों की भूमिका बताई। मामले में 2019 में NIA द्वारा गिरफ्तार चारों आरोपियों को जमानत मिल गई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग को ही खारिज कर दिया है, जिसके बाद चारों आरोपी पूरी तरह बरी हो गए हैं।

जांच एजेंसियों की अलग-अलग थ्योरी से उठे थे सवाल

ATS द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नूर-उल-हुदा, शब्बीर अहमद (अब मृत), रईस अहमद, सलमान फारसी, फारोग मगदूमी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद और अबरार अहमद शामिल थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है जबकि बाकी सभी बरी हो चुके हैं। करीब 20 साल तक चले इस मामले में जांच एजेंसियों की अलग-अलग थ्योरी और बार-बार बदलते घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए थे।

आखिरकार सामने आया सच: महाजन

भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाजन ने कहा कि लंबे समय के बाद अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया गया था और बेगुनाह लोगों को जानबूझकर फंसाया गया था।

शिखर बैंक घोटाला मामले में रोहित पवार को क्लीन चिट

▸▸ मूल अपराध खत्म होने के आधार पर मिली राहत, ईडी का मामला भी हुआ बंद

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई की विशेष सत्र अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार और उनके सहयोगियों को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तभी टिक सकता है जब कोई मूल अपराध अस्तित्व में हो। चूंकि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मूल मामले में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल कर दी थी और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए रोहित पवार के खिलाफ ईडी का मामला तकनीकी और कानूनी रूप से स्वतः ही कमजोर हो गया। अदालत ने केवल रोहित पवार ही नहीं, बल्कि उनके करीबी सहयोगी व्यवसायी राजेंद्र इंगवले और अन्य पांच आरोपियों के आवेदनों को भी मंजूर कर लिया।

ईडी के गंभीर आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में कन्नड़ सहकारी चीनी कारखाने की नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। बैंक ने 2012 में कारखाने को कथित तौर पर वास्तविक कीमत से बहुत कम दाम में नीलाम किया। ईडी का दावा था कि नीलामी में शामिल दूसरी कंपनियां रोहित पवार की 'बारामती एग्रो' से ही जुड़ी थीं और पूरी प्रक्रिया महज एक औपचारिकता थी।

कोर्ट के रुख में बदलाव

शुरुआती जांच के दौरान, विशेष अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि 'प्रथम दृष्टया' रोहित पवार नीलामी की गड़बड़ी में शामिल लग रहे हैं। हालांकि, EOW की क्लोजर रिपोर्ट आने और कानूनी बारीकियों के विश्लेषण के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अब मामला चलाने का कोई ठोस आधार नहीं बचा है।

ब्रीफ न्यूज़

पीएम मोदी को आतंकी कहना पड़ा भारी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा ने आज पीएम मोदी को आतंकी कहने के मामले में चुनाव आयोग से खड़गे की शिकायत की थी। दरअसल खड़गे ने मंगलवार को चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को आतंकी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि PM मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं। मेरा मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं।

महाराष्ट्र इकोनॉमी की सुपर छलांग

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति ने महाराष्ट्र के लिए 2.56 लाख करोड़ के कुल निवेश वाले 18 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, जिससे राज्य में लगभग एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इन हाई-टेक परियोजनाओं में ग्रीन स्टील, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम-आयन बैटरी और रक्षा उपकरण जैसे भविष्यवादी क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इस व्यापक निवेश का उद्देश्य न केवल औद्योगिक विकास को गति देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा करना और स्थानीय कार्यबल के कौशल विकास को बढ़ावा देना भी है।

बीजेपी ने घोषित की प्रवक्ताओं की नई फौज

रवींद्र चव्हाण ने 23 प्रदेश प्रवक्ताओं और विभागीय प्रचार प्रमुखों की नियुक्तियाँ कीं

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

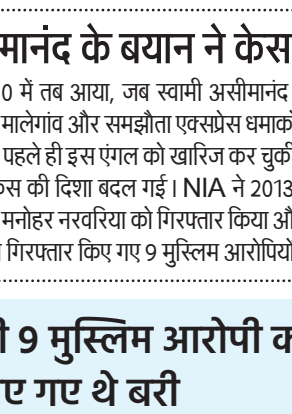

पार्टी की भूमिका को आक्रामक तरीके से रखने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने बुधवार को महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ताओं और विभागीय प्रचार प्रमुखों (प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिसिटी) के नामों की आधिकारिक घोषणा की। इसमें अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए जोश वाले कार्यकर्ताओं को मौका देते हुए पार्टी ने 23 प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज मैदान में उतारी है।

विभागीय प्रचार प्रमुखों की नियुक्ति

- कोंकण विभाग: सतीश धारप
- ठाणे विभाग: दीपेश म्हात्रे
- पालघर: समीर पाटिल
- पूर्वी विदर्भ: कल्पना नालस्कर
- पश्चिमी विदर्भ: अन्नू शर्मा
- उत्तर महाराष्ट्र: गोविंद बोरसे
- पश्चिमी महाराष्ट्र: संजय मयेकर

प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची

प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में श्वेता शालिनी, विश्वास पाठक, प्रमोद जठार, अजीत चव्हाण, अवधूत वाघ, गणेश खणकर, शिवराय कुलकर्णी, राम कुलकर्णी, अतुल शाह, विनोद वाघ, गणेश हाके और कुणाल तिलक शामिल हैं। इनके साथ ही विनायक आंबेकर, राजीव पांडे, पंकज मोदी, आसिफ भामला, जितेन गजारिया, प्रमोद राठौड़, प्रीति गांधी, शिवानी दानी, अजय पाठक, लक्ष्मण सावजी और समीर बाकरे जैसे अनुभवी नेताओं को भी प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अब कचरे से बनेगी बायोगैस

▸▸ महाराष्ट्र कैबिनेट ने बायोगैस, जमीन, आईटी पार्क और शिक्षकों के वेतन पर लिए चार अहम फैसले

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और प्रशासनिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए चार बड़े फैसलों को मंजूरी दी गयी। राज्य ने पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नयी कंप्रेस्ड बायोगैस नीति

की आधिकारिक घोषणा की है। इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हर जिले में एक समन्वय समिति स्थापित की जायेगी। इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। चालू वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र और शिक्षकों को बड़ी राहत

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सात आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब संशोधित मूल वेतन मिलेगा। इतना ही नहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की आगामी भर्ती प्रक्रिया में इन शिक्षकों को उनके अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सतारा में आईटी पार्क पुनर्गठन

सतारा जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजे नागेवाडी में आईटी पार्क (IT Park) स्थापित करने को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को 42.55 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से सतारा और आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, राजस्व विभाग ने अधिकतम जोत सीमा नियम के अनुसार, जमीन को 'भोगवटादार वर्ग-2' से 'भोगवटादार वर्ग-1' में बदलने के प्रीमियम (अधिमूल्य) को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 23-24 को रोड बंद

मुंबई। अगर आप गुरुवार या शुक्रवार मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से सफर करने का मन बना रहे हैं, तो रुकिए। एक्सप्रेसवे पर एक ब्रिज के काम की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने 'मेगा ब्लॉक' का ऐलान किया है। दोपहर के समय करीब 3 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रुकी रहेगी। 23 और 24 अप्रैल को दोपहर के समय यातायात को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। एक्सप्रेसवे पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार मेंटेनेंस और नए निर्माण कार्य किए जाते हैं। इस बार, यह ब्लॉक कुसगाव-लोनावला के पास बन रहे एक नए ब्रिज के काम के लिए लिया जा रहा है।

रणनीति

कांग्रेस और सहयोगी दलों को घेरने की योजना, उत्तर प्रदेश अगला बड़ा मोर्चा

भाजपा की दूरगामी रणनीति का हिस्सा बना महिला आरक्षण का मुद्दा

एजेंसी । नई दिल्ली

महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में गिरने को भाजपा ने एक अवसर के रूप में लिया है। पार्टी ने इसे अपनी लंबी राजनीति का हिस्सा बनाते हुए देशव्यापी अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यह समझाना है कि जब तक संसद में भाजपा और राजग (NDA) को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब तक नीति-निर्धारण में महिलाओं की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा।

जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान

रणनीति के तहत पंचायत, जनपद और नगर निकायों की महिला प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में समर्थक महिलाओं के बीच जाकर माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि बड़ी संख्या में महिलाएं केंद्र सरकार की विभिन्न लाभार्थी योजनाओं (जैसे उज्ज्वला, आवास योजना आदि) से जुड़ी हैं, इसलिए पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें यह समझाने में आसानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल उनके प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं।

विपक्ष की घेराबंदी और जनमत तैयार करना

भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि विधेयक के गिरने से विपक्ष का 'महिला विरोधी' चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। पार्टी का मानना है कि भले ही महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध न करें, लेकिन वे मतदान के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इसी आक्रोश को वोट में बदलने के लिए भाजपा ने शहरी क्षेत्रों में महिला मोर्चा और ग्रामीण स्तर पर पंचायत इकाइयों को सक्रिय कर दिया है ताकि एक मजबूत जनमत तैयार किया जा सके।

यूसुफ पठान के ससुराल पक्ष ने मारपीट मामले पर दी सफाई

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद यूसुफ पठान से जुड़े पारिवारिक विवाद में नया बयान सामने आया है। उनके साले इमरान खान और सास नसीबजान ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी है।

यूसुफ पठान के साले इमरान खान ने कहा कि शनिवार रात हुई झड़प कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि यह दोनों पक्षों के बीच 10-12 साल पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में बेवजह यूसुफ पठान का नाम घसीटा जा रहा है, जबकि उनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। इमरान खान के मुताबिक, यह सब सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है।

तीनों रिश्तेदारों की जमानत याचिका खारिज

तीनों आर्थर रोड जेल में बंद हैं

वहीं, माजगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के तीनों आरोपी रिश्तेदारों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन आरोपियों पर अपने पड़ोसी पर हमला करने का आरोप है। तीनों आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

बच्चों के बीच शुरू हुआ था झगड़ा

यूसुफ पठान की सास नसीबजान ने कहा कि झगड़ा बच्चों के बीच शुरू हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके दामाद को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। उनका कहना है कि चुनाव के माहौल में जानबूझकर इस मामले को तूल देकर यूसुफ पठान की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सोमवार को सांसद यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान, साले उमरशाद खान और एक अन्य रिश्तेदार शोएब खान को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज है। पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना शनिवार रात करीब 9 बजे भायखला इलाके में हुई। स्थानीय निवासी यूसुफ खान अपनी कार से घर लौट रहे थे। सड़क पर बने एक गड्ढे के कारण कार का टायर पानी में गया और छींटे पास खड़े शोएब खान पर पड़ गए। यूसुफ खान का दावा है कि उन्होंने तुरंत गाड़ी रोककर माफी मांगी, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय हिंसक हो गया। आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद शोएब ने गाली-गलौज की और बांस की लकड़ी से कार का विंडशील्ड तोड़ दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब यूसुफ खान पुलिस स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान से हुई। आरोप है कि खालिद खान, उनके बेटे उमरशाद और अन्य साथियों ने यूसुफ खान के परिवार पर बांस की लाठियों और बेसबॉल बैट से हमला कर दिया।

नासिक-सिन्नर धोखाधड़ी केस का ठाणे कनेक्शन उजागर

- सेवानिवृत्त मनपा अधिकारी पर गंभीर आरोप
- कासरवडावली पुलिस ने शुरू की जांच

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

नासिक-सिन्नर में सामने आए कथित धोखाधड़ी और शोषण मामले के तार अब ठाणे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अशोक खरात से जुड़े इस मामले में ठाणे के कासरवडावली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। शिकायत के अनुसार, ठाणे महानगरपालिका के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त महेश आहेर पर महिला को कथित रूप से खरात के संपर्क में लाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आहेर के खिलाफ टॉर्चर, छेड़छाड़ और धमकी देने जैसे आरोप दर्ज किए हैं।

महिला को जबरन ले जाने और प्रताड़ना का आरोप

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आहेर उसे भरोसे में लेकर नासिक स्थित खरात के कार्यालय ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध कथित 'जादू-टोना' जैसी गतिविधियां की गईं और उसे 'मोती' पहनने के लिए मजबूर किया गया। महिला का दावा है कि इस पूरी घटना से उसे मानसिक आघात पहुंचा।साथ ही, 2020 से 2023 के बीच उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

ईडी और क्राइम ब्रांच भी सक्रिय

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी सक्रिय हो गया है और अशोक खरात के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा है। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि खरात और आहेर के बीच वित्तीय और कथित 'आध्यात्मिक' संबंध थे या नहीं। ठाणे क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। क्राइम पुलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव ने अन्य संभावित पीड़ितों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। मामले के सामने आने के बाद ठाणे मनपा सर्कल में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासों और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

भिवंडी में दो आपराधिक घटनाएं, पुलिस ने तेज की जांच

- शांतीनगर से नाबालिग लापता
- नारपोली में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

ठाणे जिले के भिवंडी शहर में दो अलग-अलग आपराधिक मामलों ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक ओर शांतीनगर इलाके से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है, वहीं दूसरी ओर नारपोली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है।

नाबालिग के अपहरण की आशंका

पहले मामले में शांतीनगर क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 21 अप्रैल 2026 की रात घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शांतीनगर पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

शादी का झांसा देकर शोषण, आरोपी फरार

दूसरे मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक युवक पर शादी का झूठा वादा कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी की पहचान पवन उर्फ राज बाबू जाधव (31) के रूप में हुई है, जो अंजुरफाटा तांडा का निवासी बताया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने 25 सितंबर 2025 से अब तक कई बार पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। यह घटनाएं मानकोली स्थित एक फ्लैट में होने का आरोप है। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने कथित तौर पर मारपीट कर संबंध से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दें, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके।

लोन इंटरेस्ट रिफंड स्कीम में बड़ा बदलाव

- अब घर बैठे पूरी होगी प्रक्रिया, पारदर्शिता और सुविधा पर जोर

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

अन्नासाहेब पाटिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की इंडिविजुअल और ग्रुप लोन इंटरेस्ट रिफंड स्कीम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए निर्णय के तहत अब लाभार्थी घर बैठे ही अपने दस्तावेजों की कमी को दूर कर सकेंगे और बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के अनुसार, लाभार्थी अपने लॉगिन के माध्यम से उन आवेदनों को देख सकेंगे जिन्हें दस्तावेजों की कमी के कारण बैंकों ने रिजेक्ट या होल्ड किया है। वे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जिसके बाद निगम द्वारा उनकी जांच की जाएगी। पात्र मामलों को 'सबमिट' विकल्प के जरिए सीधे मुख्यालय भेजा जाएगा।

15 दिनों में सुधार का मौका

अब सिस्टम में प्रत्येक होल्ड केस की स्पष्ट वजह दिखाई देगी। ऐसे मामलों में लाभार्थियों को 15 दिनों के भीतर जिला समन्वयकों से संपर्क कर त्रुटियों को सुधारना होगा। भविष्य में सभी दस्तावेज सीधे लॉगिन से अपलोड करने की सुविधा को और मजबूत करने की योजना है। पहले नियम के अनुसार, ब्याज राशि खाते में आने के बाद ही अगला दावा किया जा सकता था, लेकिन अब 'CAFCO के लिए भेजा गया' स्तर पर पहुंचते ही लाभार्थी अगला दावा प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी।

फर्जी दस्तावेजों पर सख्ती

नासिक और अहिल्यानगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद कुछ संदिग्ध आवेदनों को ब्लॉक किया गया है। जिन लाभार्थियों के विवरण में गड़बड़ी पाई गई है, उन्हें मूल दस्तावेजों के साथ तुरंत संपर्क करने को कहा गया है। निगम के प्रबंध निदेशक विजयसिंह देशमुख ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और लाभार्थी किसी भी एजेंट या अफवाहों से दूर रहें। सभी आधिकारिक जानकारी और मार्गदर्शन केवल निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उल्हासनगर अस्पताल में एंबुलेंस संकट गहराया

- घंटों इंतजार में मरीज बेहाल
- स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

उल्हासनगर के जिला स्तर के मध्यवर्ती अस्पताल में एंबुलेंस की भारी कमी एक बार फिर सामने आई है। ताजा घटना में एक गर्भवती महिला को समय पर एंबुलेंस न मिलने से करीब छह घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कर्जत पुलिस मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे आठ माह की गर्भवती और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को अस्पताल लेकर आई। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे सर जे.जे. अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद 102 और 108 एंबुलेंस सेवा को बार-बार संपर्क किया गया, लेकिन करीब छह घंटे तक कोई एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। अंततः सिविल सर्जन डॉ. मनोहर बनसोडे को जानकारी देने के बाद शाम करीब 7 बजे एंबुलेंस की व्यवस्था हो सकी। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक गंभीर महिला मरीज की एंबुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल में ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सरकार की आलोचना हुई थी।

महंगी निजी एंबुलेंस बनी मजबूरी

अस्पताल के बाहर निजी एंबुलेंस उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी लागत आम लोगों के लिए काफी अधिक है। वहीं उल्हासनगर महानगरपालिका की एंबुलेंस सेवा भी जटिल प्रक्रियाओं के कारण समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने सरकारी 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मरीजों को समय पर एंबुलेंस उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं।

आधार की तकनीकी बाधा बनी त्रासदी

- नवजात की मौत से मचा आक्रोश
- एम्बुलेंस न मिलने से घर में प्रसव

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

भिवंडी तालुका के मैंदे बीजपाड़ा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की कथित लापरवाही ने एक दर्दनाक घटना को जन्म दिया, जहां समय पर इलाज न मिलने से एक नवजात की मौत हो गई। इस घटना ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय सविता विनोद रावते को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से कई बार एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन समय पर कोई मदद नहीं मिली। खराब सड़क और परिवहन के अभाव में उन्हें दाभाड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं ले जाया जा सका। मजबूरी में महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन रातभर चिकित्सा सहायता न मिलने से नवजात की अगले दिन मौत हो गई।

सोनोग्राफी न होने से बढ़ी जोखिम

घटना का एक और गंभीर पहलू यह सामने आया है कि गर्भावस्था के दौरान महिला की एक भी सोनोग्राफी नहीं कराई गई। आरोप है कि आधार कार्ड से जुड़ी तकनीकी बाधाओं के चलते जांच नहीं हो सकी, क्योंकि पति के पास आधार कार्ड नहीं था। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।

संगठनों का विरोध, कार्रवाई की मांग

भूमिपुत्र एल्गार संगठन ने इस घटना को लेकर दाभाड स्वास्थ्य केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार ने इसे 'प्रशासन की घोर लापरवाही' बताते हुए दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।

जांच शुरू, कार्रवाई का इंतजार

पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और नवजात के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। साथ ही संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर 'डिजिटल प्रक्रिया' और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करती है। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है।

भिवंडी में दो बड़ी घटनाओं से मचा हड़कंप

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

भिवंडी शहर में दो अलग-अलग घटनाओं ने कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक ओर बिजली चोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच तेज कर दी है।

पहले मामले में शांतीनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता वरद जगदीश थीगळे (27) ने आरोप लगाया कि माधव नगर स्थित एक फ्लैट में लंबे समय से अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी अंसारी जुबेर अहमद ने 6 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2026 के बीच बिजली मीटर को बायपास कर सीधे फीडर सेक्शन पिलर से कनेक्शन जोड़ लिया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने लगभग 7,526 यूनिट बिजली का अवैध उपयोग किया, जिससे 1.85 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। इस मामले में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक अरुण घोलप मामले की जांच कर रहे हैं।

बिजली चोरी का खुलासा

युवक पर जानलेवा हमला

दूसरी घटना में घुंघटनगर इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। शिकायतकर्ता संतोषकुमार केशरवाणी (39) ने बताया कि 21 अप्रैल 2026 की शाम सुंदरबेनी कंपाउंड के पास कुछ लोगों को नशा करने से मना करने पर विवाद हुआ। आरोप है कि सलील उर्फ बल्ली शेख ने चाकू से युवक विशाल के सीने पर वार किया, जबकि अन्य आरोपी फैसल, साहिल उर्फ शत्रु और मोहम्मद अमरश ने लोहे के हथियारों और लात-घूंसे से हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार जारी है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक संदीप रासकर के मार्गदर्शन में जारी है। इन घटनाओं के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जबकि पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मध्य रेल
भुसावल मंडल
ई–निविदा सूचना

भारत के महामहिम राष्ट्रपति की ओर से सीनियर डिवीजनल बिजली इंजीनियर (क.वि.) मध्य रेल, भुसावल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु डीजीटेली हस्ताक्षरित ऑनलाइन ओपन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। **टेंडर नोटिस नं.:** भुसावल_ईलेक्ट_ टीआरडी_23_2026 दिनांक 20.04.2026, **कार्य का नाम:** अकोला स्टेशन पर माल गोदाम की स्थापना/हटाने की सुविधा के लिए यूपी शंटिंग नेक को पूरी रेक लंबाई तक विस्तारित करने के संबंध में 25 केवी, सिंगल फेज, एसी ओएचई कार्यों का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना। **कार्य की लागत:** 47,87,730/-, **बयाना राशि:** रु. 95,800/-, **निविदा जमा करने की अंतिम तारीख/समय:** 15.05.2026 को 15:00 बजे तक, **अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाइट का पता:** www.ireps.gov.in DE/07

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग
निविदा सूचना संख्या सोला–एन–टी–2026–2027–03 दिनांक 21.04.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से डीआरएम (एस एंड टी) कार्यालय, मध्य रेलवे, सोलापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित करता हैं: **इलाके के साथ काम का नाम:** मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल के लातूर–लातूर रोड खंड में घरनी (प्रस्तावित नया ब्लॉक स्टेशन) में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करना। **निविदा संख्या:** सोला–एन–टी–2026–2027–03, **कार्य की अनुमानित लागत:** रु. 8,67,22,898.49, **टेंडर फॉर्म की कीमत:** NIL **जमा की जाने वाली धरोहर राशि की अवधि:** रु. 17,34,500/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 12 महीने, **निविदा के समापन की तिथि और समय:** 15.05.2026 after 15:30 hrs. विवरण ireps वेबसाइट में उपलब्ध हैं। शुद्धिपत्र/संशोधन यदि कोई हो तो केवल उपरोक्त ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। केवल ऑनलाइन निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। मैनुअल/डाक/ई–मेल, फैक्स, हस्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के साथ तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करें और इसे **www.ireps.gov.in** पर पंजीकृत करें। बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से या बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और मूल बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (अर्थात् बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर) जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** देखें।

मंडल रेल प्रबंधक, मध्य रेलवे, सोलापुर
DE/Sur-20

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

मध्य रेल
सामग्री के प्रापण हेतु
निविदा सं. 05/2026 दिनांक 20.04.2026

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, मुंबई डिविजन, छ.शि.म.ट., मुंबई द्वारा निम्नलिखित मद के लिए इलेक्ट्रॉनिक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

निविदा सं.: 92255854B	धरोहर राशि: रु. 7,42,780/-	खुलने की तिथि: 11.05.2026

विवरण	मात्रा
आइटम संख्या–1: एक पोर्टेबल, ऑल–इन–वन डेटा स्टोरेज और नेटवर्क टेस्टिंग टर्मिनल, जिसमें कम से कम ये स्पेसिफिकेशन्स हों: 12GB RAM, 256 GB स्टोरेज, 13वीं जेनरेशन का Intel Core i5 प्रोसेसर (या Mac में इसके बराबर का प्रोसेसर), Windows 11 Pro (या iOS में इसके बराबर का OS), एंटी–ग्लेयर IPS 1080p FHD डिस्प्ले और वायरलेस कीबोर्ड व माउस का कॉम्बो। निर्माता: IBM, HP, Dell, Apple, Vaio, Samsung, Toshiba या Microsoft. [वारंटी अवधि: डिलीवरी की तारीख से 30 महीने]	10 नग
आइटम संख्या–2: ऊपर बताए गए उपकरणों के जरिए स्टेशनों / DG / SHY के बीच वॉइस कम्युनिकेशन की सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग और वॉइस लॉगिंग के लिए सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सप्लाई। न्यूनतम तकनीकी स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:– प्रोसेसर–Intel Core TM i7-6700T या उससे बेहतर, मेमोरी: 16GB, हार्ड ड्राइव: 1 TB SSD, ग्राफिक्स कार्ड: NVIDIA GeForce GT 730 (4 GB DDR3 डेडिकेटेड) नेटवर्किंग 802 m, 11 b/g/n (IXI) और Bluetooth 4.0 M. 2 कॉम्बो, साउंड कार्ड: DTS Studio Sound TM, कीबोर्ड और माउस: वॉल्यूम कंट्रोल के साथ HP USB वायर्ड कीबोर्ड, 3 पावर सप्लाई: 180W AC पावर एडॉप्टर, ऑडियो: DTS Sound TM, मेमोरी स्लॉट: 2 DIMM, बाहरी I/O पोर्ट: 2 USB 3.0; 4 USB 2.0 DIMM, Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, LED मॉनिटर: 24 (23.08") 24 es slim Full HD IPS. **(II).** सर्च, सिंक, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा बैकअप सुविधा के साथ सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सर्वर सॉफ्टवेयर। **(III).** 1.2 mm मोटी स्टील की 19" रैक, 600 mm W X 32 UH X 600 mm D, पूरी तरह से पावर कोटेड। दरवाज़े/पैनल अलग किए जा सकने वाले, आगे और पीछे के दरवाज़ों में लॉकिंग की व्यवस्था, 4 कैस्टर। एक स्लाइडिंग कीबोर्ड शेल्फ, 4 अलग की जा सकने वाली ट्रे, 5 एम्प्स के 5 सॉकेट के साथ AC पावर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था, अर्थिंग डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था, केबल/रूट मैनेजर। [वारंटी अवधि: डिलीवरी की तारीख के बाद 30 महीने].	05 नग
आइटम संख्या–3: RDSO/ SPN/TC/38-2002 Ver 2 या उसके बाद के संस्करण के अनुसार 02 चैनल वाले Voice Data Recording and Processing Unit (VDRPU) की आपूर्ति और स्थापना; इसके साथ 12V/15A SMPS, 12V/65AH SMF बैटरी, GPS घड़ी (HH:MM 20 mm, SS 14mm), और 19" 6U Rack भी शामिल होंगे। [वारंटी अवधि: डिलीवरी की तारीख के बाद 30 महीने].	99 नग
आइटम संख्या–4: स्टेशन के VHF उपकरणों के रेडियो कवरेज क्षेत्र के भीतर होने वाले संचार को रिकॉर्ड करने के लिए VHF रिसीवर की आपूर्ति और स्थापना। यह रिसीवर निम्नलिखित के साथ काम करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए:– (i) ऊपर आपूर्ति किया गया 2–चैनल VDRPU. (ii) RDSO/SPN/TC/ 107/2018 Ver 2.1 या उसके बाद के संस्करण के अनुसार VHF रेडियो। [वारंटी अवधि: डिलीवरी की तारीख के बाद 30 महीने].	99 नग

नोट: 1. उपरोक्त निविदाएं IREPS वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड कर दी गई हैं। फर्म, जो उपरोक्त ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक हों, को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर अपना इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण करा लें। इस ई–निविदा के लिए हस्तलिखित निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। **2.** निविदादाताओं को धरोहर राशि का भुगतान IREPS के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। **3.** इन निविदाओं के विवरण तथा अन्य शर्तों हेतु IREPS कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखें। **4.** किसी शंका हेतु कृपया वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, मुंबई डिवीजन, छ.शि.म.ट., मुम्बई–400001 को लिखें। ई–मेल: **srdmm@bb.railnet.gov.in** **नोट: यह निविदा सार्वजनिक खरीदनीति आदेश 2017/ दिनांक 15.06.2017 का अनुपालन करती है।**
DE-72

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

'बड़ी रैली में जाम तो लगेगा ही'

ट्रैफिक जाम मामले में मंत्री गिरीश महाजन का सफाईनामा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

वर्ली इलाके में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आयोजित भाजपा की रैली के दौरान एक महिला और मंत्री गिरीश महाजन के बीच हुई तीखी बहस का मामला अब गरमा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को मंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए घटना पर सफाई दी, जिसमें उन्होंने महिला के गुस्से को जायज तो बताया, लेकिन उनके व्यवहार पर सवाल भी उठाए। गिरीश महाजन ने बताया कि यह कार्यक्रम कांग्रेस के विरोध में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े आंदोलनों के दौरान सड़क पर यातायात प्रभावित होना और लोगों को असुविधा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, ₹जब हम कोई बड़ा मार्च निकालते हैं, तो थोड़ी परेशानी तो होती ही है। इतिहास में भी ऐसे कई बड़े आंदोलन हुए हैं जो कई दिनों तक चले थे।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मंगलवार को भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष को घेरने के लिए रैली निकाली थी। इससे सड़क पर जाम लग गया। उसी समय एक महिला वहां पहुंची और चिल्लाने लगी कि आप लोग यहां से हटिए आपकी वजह से जाम लगा है। महिला ने सवाल उठाया कि इस तरह के प्रदर्शन किसी खुले मैदान में क्यों नहीं किए जाते। महिला के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी।

कांग्रेस का हमला

इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं को गुमराह कर रही है और आम जनता को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ महाजन ने कहा कि छोटे कार्यक्रमों और इतने बड़े मोर्चे की तुलना करना गलत है क्योंकि हजारों लोगों के आने पर व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण होता है।

मंत्री महाजन ने क्या कहा?

महाजन ने कहा कि ट्रैफिक जाम की बात सही है, लेकिन महिला का व्यवहार उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों पर बोतलें फेंकी। उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ भी गलत व्यवहार किया। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, ₹मैं समझता हूं कि वह अपने बच्चे को लेने की जल्दी में थी, और उसका गुस्सा कुछ हद तक जायज है। मैंने खुद उस महिला को भरोसा दिलाया था कि हम अगले 10 मिनट में रास्ता साफ कर देंगे। मैंने उन्हें हुई असुविधा के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी भी मांगी थी। मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।₹ मंत्री महाजन के अनुसार, इस मोर्चे में करीब 15 से 20 हजार महिलाएं शामिल थीं। महाजन ने वीआईपी कल्चर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शन की अनुमति पहले ही ली गई थी।

शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंदरों के आतंक पर लगाम लगाने की तैयारी

बंदर पकड़ो, इनाम पाओ...

सरकार ने हटाई इनाम की सीमा, अब हर बंदर पर मिलेंगे 600

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई सहित महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंदरों और लंगूरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ और खेती को होने वाले नुकसान को देखते हुए राज्य के वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

सरकार ने अब बंदरों को पकड़ने वालों के लिए इनाम की राशि के नियमों में बदलाव किया है, ताकि इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। वन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब कितने भी बंदर पकड़े जाएं, प्रति बंदर 600 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2025 में लागू किए गए पुराने नियमों के तहत इनाम की राशि को अधिकतम 10,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया था। पुराने नियम के मुताबिक, 10 से अधिक बंदर पकड़ने पर प्रति बंदर मिलने वाली राशि को घटाकर 300 रुपये कर दिया जाता था, लेकिन विधायकों की मांग के बाद अब इसे समान रूप से 600 रुपये कर दिया गया है।

खेती और शहरी संपत्तियों का भारी नुकसान

गाँवों में बंदरों और लंगूरों द्वारा फसलों और बगीचों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया जाता है। वहीं, मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में भी इनका उत्पात बढ़ गया है। स्थिति यह है कि निवासियों को अपने खिड़की-दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ते हैं। सोसायटियों में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने और गैलरी में सूख रहे कपड़े फाड़ने जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरे के कारण वन विभाग ने स्थानीय निकायों को इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

10 किमी दूर जंगलों में होगा पुनर्वास

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। पकड़े गए प्रत्येक बंदर या लंगूर का फोटो या वीडियो रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि कोई बंदर घायल पाया जाता है, तो उसे उचित उपचार दिया जाएगा।

150 डबलडेकर बसों का इंतजार खत्म

बेस्ट ने ठेकेदार को दिया अल्टीमेटम

मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली 'बेस्ट' के बेड़े में 150 नई डबलडेकर बसों का शामिल होना पिछले दो वर्षों से लटका हुआ है। बार-बार नोटिस देने के बावजूद ठेकेदार कंपनी बसों की आपूर्ति करने में विफल रही है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बेस्ट की महाप्रबंधक सोनिया सेठी ने स्पष्ट किया है कि यदि अगले एक महीने के भीतर कंपनी ने कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया या आपूर्ति नहीं दी, तो उनका अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) रद्द कर दिया जाएगा।

ढाई साल पहले दिया था ऑर्डर, अब तक केवल 50 बसें आई

बेस्ट प्रशासन ने करीब ढाई साल पहले यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए 200 वातानुकूलित (AC) डबलडेकर बसों का ऑर्डर दिया था। हालांकि, अब तक केवल 50 बसें ही बेड़े में शामिल हो पाई हैं। शेष 150 बसों की अनुपस्थिति के कारण प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार मोहलत देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया है।

50 मिनट तक पहुँचा वेटिंग टाइम

बसों की कमी का सीधा असर मुंबई के आम यात्रियों पर पड़ रहा है। कई लोकप्रिय रूटों पर बसों की संख्या कम होने के कारण लोगों को बस स्टॉप पर लंबा इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल कुछ मार्गों पर प्रतीक्षा समय (वेटिंग टाइम) बढ़कर 50 मिनट तक पहुँच गया है। सोनिया सेठी ने बेस्ट समिति की बैठक में बताया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा और समय सीमा समाप्त होते ही नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सुरक्षा नियमों और लागत ने बिगाड़ा खेल

बेस्ट ने इन बसों के लिए 'स्विच मोबिलिटी' कंपनी के साथ समझौता किया था। देरी का एक मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा 2019 में लागू किए गए नए सुरक्षा नियम हैं। अब सार्वजनिक वाहनों, विशेषकर डबलडेकर बसों में 'इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल यूनिट' लगाना अनिवार्य है। यह उपकरण मोड़ लेते समय इंजन को नियंत्रित कर बस को पलटने से बचाता है।

अनिल देशमुख की याचिका पर ईडी को नोटिस

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों (Charges) को तय किए जाने पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की है।

देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत को ईडी मामले में आगे बढ़ने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले का निपटारा करना चाहिए, क्योंकि वही मुख्य अपराध है। वकील ने दलील दी कि सीबीआई ने फिलहाल केवल एक आरोप (सचिन वाजे के माध्यम से 100 करोड़ रुपये की वसूली) पर चार्जशीट दाखिल की है, जबकि शेष आरोपों की जांच अभी भी जारी है। उनका कहना था कि यदि इस स्तर पर ईडी मामले में आरोप तय किए जाते हैं, तो देशमुख का मुख्य अपराध से आरोपमुक्त होने का अधिकार छीन जाएगा।

मुंबई पुलिस बनी देवदूत

भीड़ में खोई 8 साल की मासूम को एएसआई चेतना ने सुरक्षित माता-पिता से मिलाया

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई की भीड़भाड़ और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे व्यस्त इलाके में अपनों से बिछड़ना किसी भी परिवार के लिए दुःस्वप्न जैसा होता है। औरंगाबाद से आए एक परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस की संवेदनशीलता और ASI चेतना औतगाडे की सतर्कता ने महज चंद घंटों में इस अनहोनी को सुखद अंत में बदल दिया। सुबह के वक्त, जब CSMT सब-वे यात्रियों की भारी भीड़ से भरा था, सहायक उप-निरीक्षक चेतना औतगाडे की नज़र एक डरी हुई और रोती हुई 8 साल की बच्ची पर पड़ी। बच्ची की पीठ पर काला बैग था और वह काफी घबराई हुई थी। ASI औतगाडे ने न केवल उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया, बल्कि एक माँ की तरह उसे शांत कराकर उसका भरोसा जीता।

भावुक पुनर्मिलन

बच्ची के पिता और चाचा जब उसे खोजने के लिए दर-दर भटक रहे थे, तब उन्हें आजाद मैदान थाने में अपनी लाडली के सुरक्षित होने की खबर मिली। अपनी बच्ची को सही-सलामत देखकर पिता की आँखों से आँसू छलक पड़े। परिवार ने गदगद होकर कहा कि मुंबई पुलिस की तत्परता की वजह से ही आज हमारी दुनिया उजड़ने से बच गई।

'मुंबई इन मिनट्स' जैसा सर्च ऑपरेशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए आजाद मैदान पुलिस स्टेशन और पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई के कार्यालय के बीच त्वरित तालमेल बैठाया गया। मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी कृष्णदर्शन जाधव ने पुलिस तंत्र के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन को गति दी, जिससे सूचना का आदान-प्रदान तेज़ हुआ। सहायक पुलिस निरीक्षक शिंदे की टीम ने रेलवे और मेट्रो परिसरों में तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया। लगातार लाउडस्पीकर पर घोषणाएँ की गईं। इस व्यापक सर्च के दौरान ही पता चला कि बच्ची पहले से ही सुरक्षित पुलिस हिरासत में है।

डीए बढ़ोतरी में देरी से रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश

'काली पट्टी' बांधकर जताया विरोध

मुंबई । मुंबई के नगर निकाय (बीएमसी) अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार को एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। जुलाई 2024 से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी लागू न होने के कारण डॉक्टरों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। विरोध स्वरूप डॉक्टरों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना काम जारी रखा, ताकि मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए। डॉक्टरों का कहना है कि अब तक उनकी मांगें केवल बैठकों और ज्ञापनों तक सीमित थीं, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता के कारण अब उन्हें सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। 'बीएमसी मार्ड' के नेतृत्व में करीब एक हजार रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मुंबई के इन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों, जैसे केईएम, बीवाईएल नायर, सायन और कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों को मजबूती से रखा।

शुक्रवार से तेज होगा आंदोलन

हालांकि बुधवार का प्रदर्शन शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक था, लेकिन 'मार्ड' ने प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है। मार्ड का कहना है कि हमने लंबे समय तक धैर्य रखा है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो शुक्रवार से यह आंदोलन पूर्ण विरोध प्रदर्शन में बदल जाएगा, जिसमें और भी अधिक संख्या में डॉक्टर शामिल होंगे।

क्या है विवाद की मुख्य वजह?

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किए जाने के बावजूद, बीएमसी के तहत आने वाले डॉक्टरों के लिए जुलाई 2024 से लंबित डीए बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है। देरी के कारण डॉक्टरों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनका एरियर (बकाया राशि) बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि अन्य क्षेत्रों में समान लाभ दिए जा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाले इन डॉक्टरों की अनदेखी की जा रही है। अगस्त 2025 से लगातार फॉलो-अप के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

धर्मांतरण, कानून और ड्रग्स के मामलों को लेकर सरकार की आलोचना

मुंबई! समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में धर्मांतरण, कानून और ड्रग्स के मामलों को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। धर्मांतरण पर बोलते हुए अबू आजमी ने कहा कि पुणे, नागपुर और नासिक जैसे शहरों में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई है।

उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया और खास तौर पर नासिक के मामले को फर्जी करार दिया। उनका कहना है कि असल में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उनके रोजगार पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। अबू आजमी ने कॉर्पोरेट कंपनियों में नमाज पढ़ने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी 5 मिनट के लिए ऑफिस में नमाज पढ़ता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब कंपनियों में गणपति उत्सव या दूसरे धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं, तो फिर नमाज का विरोध क्यों किया जाता है।

आरएसएस प्रमुख के पद पर किसी महिला को नियुक्त करके दिखाएं : सपकाल

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'महिला विरोधी विचारधारा' वाला बताया। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वे महिलाओं को हीन समझने वाले अपने मूल साहित्य को सार्वजनिक रूप से खारिज करें। सपकाल ने कहा कि भाजपा को महिला आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने चुनौती दी कि भाजपा को पहले 'मनुस्मृति' और आरएसएस के पूर्व प्रमुख एम. एस. गोलवलकर की पुस्तक 'बंच ऑफ थॉट्स' को सार्वजनिक रूप से खारिज कर देना चाहिए। उनका आरोप है कि इन साहित्यों में महिलाओं को हीन समझा गया है और भाजपा की मूल विचारधारा यहीं से प्रेरित है। भाजपा पर तंज कसते हुए सपकाल ने कहा, ₹अगर भाजपा में वाकई हिम्मत है, तो उन्हें आरएसएस (RSS) प्रमुख के पद पर किसी महिला की नियुक्ति करनी चाहिए।₹ उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि उनके शीर्ष नेतृत्व और वैचारिक संगठनों में महिलाओं को निर्णायक पदों पर क्यों नहीं रखा जाता?

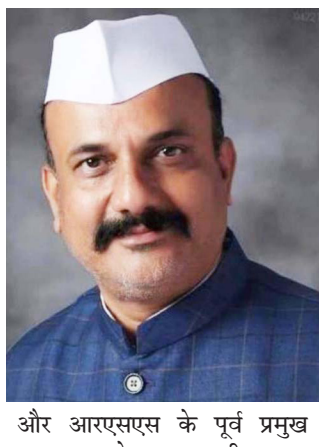

वर्ली घटना और पत्रकारों को धमकी

हाल ही में वर्ली में मंत्री गिरीश महाजन पर एक महिला के भड़कने का वीडियो वायरल हुआ था। सपकाल ने आरोप लगाया कि इस घटना से हुई शर्मिंदगी के बाद भाजपा कार्यकर्ता उन पत्रकारों और संवाददाताओं को धमका रहे हैं जिन्होंने इस वीडियो को फिल्माया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो कांग्रेस और न ही मीडिया ऐसी धमकियों से डरेगा।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% और फिर इसे बढ़ाकर 50% करने का ऐतिहासिक काम उनकी पार्टी ने किया है।

जेनेलिया-रितेश देखमुख बने 'लालपरी' के ब्रांड एंबेसेडर

मुंबई। बॉलीवुड के पावर कपल रितेश और जेनेलिया देशमुख को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) और राज्य परिवहन विभाग ने अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में इस 5 वर्षीय अनुबंध पर मुहर लगाई गई। इस पहल का मुख्य लक्ष्य सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता फैलाना और एसटी बसों (लाल परी) के सफर को सुरक्षित और लोकप्रिय बनाना है।

इस मौके पर अभिनेता रितेश देशमुख काफी भावुक दिखे। उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि एसटी बस के साथ उनका गहरा भावनात्मक रिश्ता है।

सीबीआई ने नासिक के दो स्कूल अधिकारियों पर दर्ज किया मामला

जांच बंद करने के नाम पर माँगी थी रिश्वत

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नासिक स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के दो अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने स्कूल के एक लैब अटेंडेंट के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को बंद करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी।

ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुला राज

प्राथमिक जांच (FIR) के अनुसार, शिकायतकर्ता ने जब अपनी जांच बंद कराने के संबंध में आरोपियों से मुलाकात की, तो उन्होंने रिश्वत की मांग रखी। 12 अप्रैल को हुई मुलाकात के दौरान आरोपियों ने 40,000 की मांग की और कहा कि यह राशि दोनों अधिकारियों के बीच बराबर बांटी जाएगी। शिकायतकर्ता ने इस पूरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसे उसने सीबीआई को सौंप दिया। मंगलवार को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में सीबीआई ने इन आरोपों का सत्यापन किया। रिकॉर्ड की गई बातचीत से स्पष्ट हुआ कि आरोपी जांच को रफा-दफा करने के लिए पैसे मांग रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।

क्या है मामला ?

सीबीआई के अनुसार, यह कार्रवाई नासिक के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) में कार्यरत एक लैब अटेंडेंट द्वारा 21 अप्रैल को दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी। उसे जांच समिति के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।

संपादकीय

कचरे से कंचन की ओर महाराष्ट्र का बढ़ता कदम

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा आज 'संपीडित बायोगैस नीति-2026' को दी गई मंजूरी राज्य के विकास इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ साबित होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय केवल शहरी कचरे के निस्तारण का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करता है। राज्य में प्रतिदिन पैदा होने वाले हजारों टन जैविक कचरे को अब एक बोझ के बजाय एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जाएगा, जिससे न केवल डंपिंग ग्राउंड्स की समस्या कम होगी, बल्कि मीथेन जैसी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भी भारी कटौती संभव हो सकेगी। यह नीति केंद्र सरकार के 'सतत' (SATAT) पहल को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो महाराष्ट्र को हरित ऊर्जा का केंद्र बनाने का सामर्थ्य रखती है। इस नीति की सबसे व्यावहारिक खूबी इसका वित्तीय और तकनीकी ढांचा है, जिसे क्लस्टर मॉडल और हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर आधारित रखा गया है। छोटे नगर निकायों के लिए अकेले बड़े संयंत्र लगाना असंभव था, लेकिन क्लस्टर पद्धति से अब कई पंचायतें और नगर पालिकाएं मिलकर कचरा प्रबंधन कर सकेंगी। सरकार द्वारा घोषित 500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष और 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' का प्रावधान निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। इसके साथ ही, बंजर भूमि पर नेपियर घास उगाने का प्रस्ताव ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकता है। यह न केवल कचरे का प्रबंधन करेगा, बल्कि किसानों को उनकी अनुपयोगी भूमि से आय का एक नया और स्थायी स्रोत भी प्रदान करेगा, जिससे कृषि और उद्योग के बीच एक नया तालमेल स्थापित होगा। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कचरे के पृथक्करण यानी 'सोर्स सेग्रिगेशन' की सटीकता पर निर्भर करती है। बायोगैस संयंत्रों की कार्यक्षमता के लिए गीले कचरे का शुद्ध रूप में मिलना अनिवार्य है, जो वर्तमान में नगर निकायों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

जिला स्तरीय समितियों और स्थानीय प्रशासन को अब केवल संयंत्र लगाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें जन-जागरूकता के माध्यम से कचरा फेंकने की आदतों में बदलाव लाना होगा। यदि कचरा संग्रहण की श्रृंखला में कहीं भी चूक होती है, तो करोड़ों रुपये का निवेश तकनीकी बाधाओं की भेंट चढ़ सकता है। इसलिए, तकनीक के साथ-साथ नागरिक सहभागिता को इस नीति का अनिवार्य अंग बनाना होगा ताकि संचालन में निरंतरता बनी रहे। निष्कर्षतः, महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला 'सर्कुलर इकोनॉमी' के सिद्धांतों को धरातल पर उतारने का एक साहसी प्रयास है। कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाने की यह प्रक्रिया आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करेगी और मिट्टी की सेहत सुधारने में भी सहायक होगी। यह नीति स्पष्ट करती है कि भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का समाधान प्रकृति के करीब रहकर और कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण में ही छिपा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, तो महाराष्ट्र स्वच्छ भारत अभियान के अगले चरण में पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करेगा। अब समय घोषणाओं से आगे बढ़कर क्रियान्वयन की गति को तेज करने का है, ताकि 'कचरा मुक्त महाराष्ट्र' का सपना साकार हो सके।

शख्सियत — सुल्तान हैदर अली

अदम्य साहसी और धर्मनिरपेक्ष योद्धा

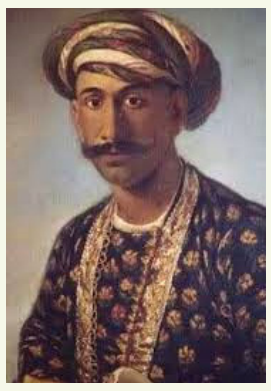

मैसूर साम्राज्य के इतिहास में हैदर अली एक ऐसा नाम है जो अदम्य साहस, असाधारण सैन्य रणनीति और धर्मनिरपेक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। हैदर अली का जन्म 23 अप्रैल, 1721 को कर्नाटक के कोलार जिले के बुदीकोट में हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब भारत विदेशी शक्तियों और आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था, तब हैदर अली ने एक साधारण सैनिक से सुल्तान तक का सफर तय कर अपनी योग्यता का लोहा मनवाया।

उनका जीवन हमें सिखाता है कि ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुल या जाति नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और योग्यता की आवश्यकता होती है। हैदर अली की बहादुरी और युद्ध कौशल अद्वितीय था। वे अपनी कुशल घुड़सवार सेना और छापामार युद्ध नीति के लिए जाने जाते थे। प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों को धूल चटाई और मद्रास (चेन्नई) के दरवाजों तक पहुंच गए, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर खौफ पैदा कर दिया था। वे भारत के उन शुरुआती शासकों में से थे जिन्होंने यह समझा कि अंग्रेजों को केवल बहादुरी से नहीं, बल्कि आधुनिक सैन्य तकनीक और अनुशासित सेना से ही हराया जा सकता है। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित किया और रॉकेट तकनीक का युद्ध में पहली बार प्रभावी उपयोग किया, जिसे बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने वैश्विक पहचान दिलाई।

हैदर अली की देशभक्ति संकुचित नहीं थी। वे जानते थे कि विदेशी ताकतें भारत के लिए एक बड़ा खतरा हैं। उन्होंने मराठों और निजाम के साथ अपने मतभेदों को भुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का निरंतर प्रयास किया। उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण यह है कि उन्होंने समुद्र की शक्ति को पहचाना और एक शक्तिशाली नौसेना बनाने की दिशा में काम किया, ताकि समुद्री रास्तों से आने वाले दुश्मनों को रोका जा सके। उनका पूरा जीवन रणभूमि में मातृभूमि की रक्षा करते हुए बीता और उन्होंने कभी भी विदेशी आधिपत्य के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी प्रशासनिक निष्पक्षता और धार्मिक सहिष्णुता आज के युग के लिए भी एक मिसाल है। एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद उनके दरबार और सेना में हिंदू अधिकारियों को ऊंचे पदों पर आसीन किया गया था। उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में खांडे राव और पूर्णैया जैसे नाम शामिल थे। उन्होंने मंदिर और मठों को दान दिया और कभी भी धर्म के आधार पर अपनी प्रजा के बीच भेदभाव नहीं किया। उनके शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों पर भगवान शिव, पार्वती और विष्णु के चित्र अंकित थे, जो उनकी सर्वधर्म समभाव की नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उनके लिए न्याय सर्वोपरि था और वे अपराधी के पद या प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सजा देने में विश्वास रखते थे।

हैदर अली का व्यक्तित्व जितना कठोर युद्ध के मैदान में था, उतना ही संवेदनशील अपनी प्रजा के प्रति था। उन्होंने कृषि सुधारों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जिससे मैसूर एक समृद्ध राज्य बना। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और देश के प्रति वफादारी को बनाए रख सकता है। 7 दिसंबर, 1782 को द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन एक निडर योद्धा, निष्पक्ष शासक और महान देशभक्त के रूप में उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।

भारत में भीषण गर्मी

बढ़ता संकट, आंकड़ों की चेतावनी और समाधान

डॉक्टर बबलू सोनकर
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेजा प्रयागराज

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, देश में हीटवेव की घटनाओं की संख्या और अवधि दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2010 के बाद से हीटवेव वाले दिनों में लगभग 20–30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन का संकेत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके प्रभाव अत्यंत चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, वर्ष 1992 से 2020 के बीच भारत में हीटवेव के कारण 24,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2015 भारत के लिए सबसे घातक रहा, जब लगभग 2,500 लोगों की जान चली गई। हाल के वर्षों में भी हर गर्मी के मौसम में सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें सामने आती हैं।

भारत में भीषण गर्मी अब केवल एक मौसमी अनुभव नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में तापमान के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। कई राज्यों में पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, देश में हीटवेव की घटनाओं की संख्या और अवधि दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2010 के बाद से हीटवेव वाले दिनों में लगभग 20–30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन का संकेत है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके प्रभाव अत्यंत चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, वर्ष 1992 से 2020 के बीच भारत में हीटवेव के कारण 24,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2015 भारत के लिए सबसे घातक रहा, जब लगभग 2,500 लोगों की जान चली गई। हाल के वर्षों में भी हर गर्मी के मौसम में सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें सामने आती हैं। अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर और बेहोशी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। विशेष रूप से मजदूर, ट्रैफिक पुलिस, रिक्शा चालक, डिलीवरी कर्मी और निर्माण कार्य में लगे लोग सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी भीषण गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, तापमान में हर 1 डिग्री वृद्धि के साथ मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन के मामलों में 3–5 प्रतिशत तक वृद्धि होती है। नींद की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। गर्म रातों के कारण शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता, जिससे कार्यक्षमता घटती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। पर्यावरणीय प्रभाव और भी व्यापक हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 60 करोड़ लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। गर्मी के कारण नदियां, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या गंभीर हो जाती है। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई शहरों में पानी की सप्लाई

सीमित करनी पड़ रही है। इसके साथ ही बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023 में भारत की अधिकतम बिजली मांग 230 गीगावॉट के पार पहुंच गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें एयर कंडीशनर और कूलर के बढ़ते उपयोग की बड़ी भूमिका है।

शहरी क्षेत्रों में "हीट आइलैंड प्रभाव" इस संकट को और बढ़ा रहा है। मुंबई, दिल्ली, नागपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया जाता है। कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें और हरियाली की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। एक अध्ययन के अनुसार, जिन क्षेत्रों में हरित आवरण अधिक होता है, वहां तापमान 2–3 डिग्री तक कम पाया गया है। लेकिन शहरीकरण के कारण पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है।

भीषण गर्मी से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक वयस्क व्यक्ति को गर्मी के मौसम में प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचना चाहिए। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनना, सिर को ढकना और धूप से सीधा संपर्क कम करना जरूरी है। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और फलों का सेवन शरीर को ठंडा रखने में सहायक होता है। साथ ही तैलीय और भारी भोजन से बचना चाहिए।

सरकारी स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश के कई शहरों में "हीट एक्शन प्लान" लागू किए गए हैं। अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान एक सफल उदाहरण माना जाता है, जिसके लागू होने के बाद गर्मी से होने वाली मौतों में लगभग 20–25 प्रतिशत तक कमी आई है। इसके अलावा, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंततः, भीषण गर्मी हमें एक स्पष्ट चेतावनी दे रही है कि प्रकृति के साथ हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। यदि हम समय रहते पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और सतत जीवनशैली की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भी भयावह रूप ले सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर प्रयास करें, ताकि इस बढ़ती गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी गीता

तितिक्षा – जागृती

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

जीवन में सुख और दुःख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान-ये सब ऐसे अनुभव हैं जो हर व्यक्ति को बार-बार स्पर्श करते हैं। हम इनसे बच नहीं सकते, पर इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य समझ और नियंत्रित कर सकते हैं। यही समझ "तितिक्षा" का मूल है। तितिक्षा का अर्थ केवल सहन करना नहीं, बल्कि सजग रहकर जीवन के उतार-चढ़ाव को समत्व भाव से स्वीकार करना है। जब मन जागृत होता है, तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका साक्षी बनकर स्थिर रहता है।

"मात्राः स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत-उष्ण सुख-दुःखदाः।
आगम-अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत॥"

इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों और बाहरी वस्तुओं के संपर्क से ही सुख-दुःख की अनुभूति होती है। ये अनुभव अस्थायी हैं-आते हैं और चले जाते हैं। परंतु अज्ञान के कारण हम इन्हें अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। वास्तव में यह मन की स्थिति है, हमारा सत्य स्वरूप नहीं। तितिक्षा हमें यही सिखाती है कि इन अनुभवों को समझें, पर उनसे बंधें नहीं। अक्सर जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है, तो हम

अत्यधिक उत्साहित होकर कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं। हम वर्तमान को भूलकर भविष्य के सुनहरे सपनों में जीने लगते हैं। वहीं, असफलता मिलने पर हम निराश होकर अपने ही छोटे से संसार में सिमट जाते हैं। यह दोनों ही स्थितियां असंतुलन की हैं। भगवान का संदेश है-इन दोनों से बचो। न तो अत्यधिक हर्ष में बहो, न ही दुःख में डूबो। तितिक्षा का अर्थ है-सतत जागरूकता। जब सुख आए, तो यह स्मरण रहे कि यह स्थायी नहीं है। जब दुःख आए, तब भी यह विश्वास बना रहे कि यह भी बीत जाएगा। इसी भाव से मन स्थिर होता है और व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। निराशा के क्षणों में स्वयं को अकेला न करें, बल्कि जीवन की प्रवाहमानता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।

जीवन ऊर्जा

विलियम शेक्सपियर: जन्म : 23 अप्रैल, 1564

जन्म

विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कालजयी नाटककार और कवि थे। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 23 अप्रैल, 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन में हुआ था। 'हैमलेट', 'मैकबेथ' और 'रोमियो-जूलियट' जैसी महान कृतियों के रचयिता शेक्सपियर का निधन भी 23 अप्रैल, 1616 को ही हुआ। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान में ही दुनिया भर में इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है, शब्द तो केवल माध्यम हैं

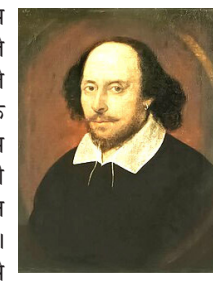

अपने स्वयं के प्रति सच्चे रहें, फिर आप किसी और के प्रति झूठे नहीं हो सकते। कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं; बहादुर केवल एक बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं। महानता से डरो मत; कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। हमारी किस्मत सितारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। सभी से प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो और किसी के साथ बुरा मत करो। बोलना कम करें, और उससे कहीं अधिक सुनें। उम्मीद ही वह एकमात्र चीज है, जो दुख के समय में हमारा हाथ थामे रखती है। बुद्धिमान खुद को मूर्ख समझता है, लेकिन मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। दुख जब आता है, तो अकेले नहीं आता, बल्कि पूरी सेना के साथ आता है। समय के साथ हम उन चीजों को खो देते हैं, जिनकी हम कद्र नहीं करते। खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। प्रेम आंखों से नहीं, बल्कि मन से देखा जाता है। यदि संगीत प्रेम का भोजन है, तो इसे बजने दें। एक छोटी सी मोमबत्ती भी बहुत दूर तक अपना प्रकाश फैलाती है; इसी तरह एक अच्छा कार्य भी इस बुरी दुनिया में चमकता है। साहस का अर्थ केवल लड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर धैर्य रखना भी है। दुनिया एक रंगमंच है, और हम सब केवल इसके पात्र हैं। अज्ञानता ही भगवान का अभिशाप है, और ज्ञान वह पंख है जिससे हम स्वर्ग तक उड़ सकते हैं। जो बीत गया है, वह केवल एक भूमिका है। अच्छाई की अधिकता कभी-कभी बुराई में बदल जाती है। संदेह हमेशा अपराधी के मन में ही बसता है। मीठे शब्द कभी-कभी कड़वे सच से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अपनी आवाज को ऊंचा करने के बजाय अपने तर्कों को मजबूत करें। सफलता के लिए तैयारी करना ही जीत की पहली सीढ़ी है। धैर्य और समय सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देते हैं।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

आत्मसंयम, समत्व और जागरूकता का पथ

भारतीय वैदिक परंपरा में जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों की दौड़ नहीं माना गया, बल्कि उसे आत्मविकास और चेतना के उत्कर्ष की यात्रा के रूप में देखा गया है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक बल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके भीतर के संतुलन, संयम और जागरूकता में निहित है। जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है, तब जीवन के उतार-चढ़ाव उसे विचलित नहीं करते, बल्कि वे उसके लिए सीख का माध्यम बन जाते हैं। वेदों में "संयम" को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

संयम का अर्थ केवल इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उचित दिशा देना है। मन, वाणी और कर्म जब संतुलित होते हैं, तब व्यक्ति का जीवन सहज और स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही "समत्व" का भाव भी उतना ही आवश्यक है। सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान-ये सभी जीवन के परिवर्तनशील पक्ष हैं। यदि मनुष्य हर परिस्थिति में समान भाव बनाए रखे, तो वह मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। वेद यह भी बताते हैं कि जागरूकता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम सजग रहते हैं, तो अपने विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं। यही समझ हमें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। बिना जागरूकता के मनुष्य परिस्थितियों का दास बन जाता है, जबकि सजग व्यक्ति परिस्थितियों के बीच भी अपने मार्ग को स्पष्ट देख पाता है। इसी वैदिक संदेश को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेरक कथा प्रचलित है।

एक गुरुकुल में दो शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों ही बुद्धिमान थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। एक शिष्य अत्यधिक उत्साही था; थोड़ी सी सफलता मिलते ही वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता और असफलता मिलने पर तुरंत निराश हो जाता। दूसरा शिष्य शांत, धैर्यवान और संतुलित था। वह हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करता। एक दिन गुरु ने दोनों को एक परीक्षा दी। उन्होंने उन्हें एक-एक दीपक दिया और कहा-"इसे लेकर वन में जाओ और बिना बुझाए वापस आओ।" दोनों शिष्य चल पड़े। कुछ ही दूरी पर तेज हवा चलने लगी। पहला शिष्य घबरा गया। वह इधर-उधर भागने लगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका दीपक बुझ गया। वह दुखी होकर लौट आया। दूसरा शिष्य धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। उसने अपने हाथों से दीपक को ढक लिया और मन को स्थिर रखा। वह न तो हवा से घबराया और न ही जल्दबाजी की। अंततः वह सुरक्षित दीपक के साथ वापस आ गया। गुरु ने उसे देखकर कहा—"यह दीपक तुम्हारे मन का प्रतीक है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में घबरा जाता है, उसका मन भी बुझ जाता है। पर जो संयम और जागरूकता बनाए रखता है, उसकी आंतरिक ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है।" यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परंतु हमारा आंतरिक संतुलन ही हमारी वास्तविक शक्ति है।

अपने विचार

भारत ने कोशिश की है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। हो सकता है कि कल ऐसा समय आए जब भारत इसमें अपनी भूमिका निभाए और सफलता भी हासिल करे। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है।

-राजनाथ सिंह
रक्षामंत्री

आज ये लोग मंगलसूत्र पर उंगली उठा रहे हैं, एकजुट नहीं हुए तो सनातन के प्राणतत्व रामायण और गीता पर भी उंगली उठाएंगे। एक बात और कान खोलकर सुन लो हमें जात-पात में नहीं बंटना है हम हिन्दू है, हम सनातनी है। चाहें कोई लाख प्रयास कर लें एकजुट होकर ही रहना है।

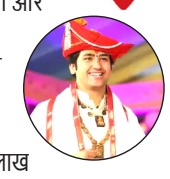

-पंडित धीरेन्द्र शास्त्री
बागेश्वर धाम

पार्टी के लोग इस खास मुद्दे पर बिल्कुल भी गुमराह न हों। स्थानीय स्तर पर होने वाली बैठकों में इस स्टैंड के बारे में विस्तार से बताएं, लेकिन ध्यान रहे कि पार्टी अनुशासन के विरुद्ध जाकर कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं करना है।

-मायावती
बसपा सुप्रीमो

न्यायाधीश को हटाने की अरविंद केजरीवाल की मांग दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होने का खतरा है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

-रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री,दिल्ली

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि." के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

नवी मुंबई मनपा के उपायुक्त कैलास गायकवाड़ पुलिस कस्टडी में

नवी मुंबई। नवी मुंबई महानगरपालिका के उपायुक्त कैलास गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने 24 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने 42 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार, अतिक्रमण विभाग से जुड़े एक बिल के भुगतान को मंजूरी देने के बदले आरोपी अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ठेकेदार दशरथ सुरवते, 15 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 के बीच ऐरोली क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी भुगतान के एवज में 42 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और मंगलवार को मनपा मुख्यालय की तीसरी मंजिल स्थित कार्यालय में गायकवाड़ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 24 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। मामले की आगे की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जा रही है, और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में ट्रैक निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

जापानी तकनीक पर आधारित J-स्लैब सिस्टम का भारत में पहली बार उपयोग

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत वायाडक्ट पर ट्रैक निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना में पहली बार जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित J-स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जो उच्च गति रेल संचालन के लिए अत्याधुनिक माना जाता है। यह ट्रैक प्रणाली आरसी ट्रैक बेड, सीमेंट एस्फाल्ट मोर्टार (CAM), प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब और फास्टनर्स सहित रेल जैसे चार प्रमुख घटकों से मिलकर बनी है। इसके लिए गुजरात में किम और आणंद में अत्याधुनिक ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की गई हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट स्लैब तैयार किए जा रहे हैं।

निर्माण कार्य की प्रगति

परियोजना के तहत अब तक 185 रूट किलोमीटर में आरसी ट्रैक बेड बिछाया जा चुका है, जबकि 188 किलोमीटर के लिए ट्रैक स्लैब तैयार हो चुके हैं। वहीं 70 किलोमीटर क्षेत्र में स्लैब बिछाने और CAM इंजेक्शन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग

ट्रैक निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह यंत्रीकृत है और इसमें विशेष मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन (FBWM) की मदद से 25 मीटर लंबी रेल को जोड़कर 200 मीटर लंबे पैनल तैयार किए जा रहे हैं, जो 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रक्रिया में जापानी संस्था JARTS द्वारा प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक स्लैब लेइंग कार (SLC) के जरिए प्रीकास्ट स्लैब को वायाडक्ट पर स्थापित किया जा रहा है, जबकि रेल फीडर कार (RFC) रेल पैनलों को बिछाने का कार्य करती है। CAM इंजेक्शन कार के माध्यम से स्लैब के नीचे मिश्रण भरकर ट्रैक की सटीक लाइन और लेवल सुनिश्चित किया जा रहा है।

बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में कदम

यह परियोजना न केवल तेज और सुरक्षित रेल सेवा सुनिश्चित करेगी, बल्कि देश में हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पूरा होने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नवी मुंबई में स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों पर विधायक मंदा म्हात्रे आक्रामक

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जल्द पूरा करने की मांग

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई में लंबित विकास कार्यों और नागरिक सुरक्षा को लेकर भाजपा विधायक मंदा म्हात्रे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने महानगरपालिका आयुक्त से मुलाकात कर बेलापुर में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और पाम बीच रोड की कमानों के मुद्दे पर प्रशासन को घेरा। मंदा म्हात्रे ने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल परियोजना कई वर्षों से लंबित है और यह शहर के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन से इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। पाम बीच रोड पर निजी कंपनी के सहयोग से बनाई गई कमानों को लेकर भी उन्होंने गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि इन संरचनाओं से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण है। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महानगरपालिका ने इन कथित खतरनाक कमानों को नहीं हटाया, तो वे आंदोलन के साथ-साथ बुलडोजर कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए वे लगातार संघर्ष करती रहेंगी।

उल्हासनगर में शिक्षकों का प्रदर्शन, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की मांग

बीएलओ और जनगणना जैसे कार्यों से बढ़ रहा बोझ
शिक्षा गुणवत्ता पर असर का आरोप

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर में शिक्षक संघों ने शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बढ़ता बोझ लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि अध्यापन के अलावा बीएलओ ड्यूटी, जनगणना और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षा क्रांति संगठन और ए-स्टेप संगठन द्वारा महानगरपालिका में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें महापौर, उप आयुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग

शिक्षक संघों ने मांग की कि शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य तक सीमित रखा जाए और अन्य कार्यों के लिए अलग कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अरुण आशान ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती कर शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इस अतिरिक्त बोझ से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

शिक्षकों ने रखे ठोस प्रमाण

बैठक के दौरान शिक्षक नेताओं ने बताया कि बीएलओ कार्य, जनगणना आदेश और सीआरसी के माध्यम से आने वाले प्रशासनिक काम शिक्षकों के मूल कार्य—शिक्षण—को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

जनसंपर्क 'लोकतंत्र का पांचवां स्तंभ'; पीआरएसआई मुंबई चैप्टर की पहल

मुंबई। के पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफमुंबई चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात उभरकर सामने आई कि आज के सूचना युग में जनसंपर्क केवल कॉर्पोरेट संचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाला 'पांचवां स्तंभ' बन चुका है। कार्यक्रम में लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिक संवाद की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संचार परिदृश्य में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करना था। इस अवसर पर जनसंपर्क क्षेत्र के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और भावी संचारकों ने एक मंच पर आकर विचार-विमर्श किया। वक्ताओं ने कहा कि संस्थाओं और नागरिकों के बीच पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही बढ़ाने में जनसंपर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रीवा-सीएसएमटी-रीवा विशेष ट्रेन का नियमित सेवाओं में रूपांतरण

मुंबई। रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और रीवा के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनों को नियमित करने का निर्णय लिया है। ये सेवाएं अब नई ट्रेन संख्या के साथ नियमित ट्रेनों के रूप में परिचालित होंगी, जिससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और ट्रेन परिचालन भी सुचारू होगा।

मौजूदा ट्रेन संख्या 02187/02188 रीवा-सीएसएमटी-रीवा साप्ताहिक विशेष ट्रेन सेवा को नियमित सेवाओं में परिवर्तित किया जाएगा । विवरण इस प्रकार है।

ट्रेन संख्या 20153 सीएसएमटी-रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस (दिनांक 24.04.2026 से सीएसएमटी से प्रभावी)। ट्रेन संख्या 20154 रीवा-सीएसएमटी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस (दिनांक 23.04.2026 से रीवा से प्रभावी)।

नियमित सेवाओं की शुरुआत के साथ विशेष ट्रेनों का निरस्तीकरण। ट्रेन संख्या 02188 सीएसएमटी-रीवा विशेष को दिनांक 24.04.2026 से निरस्त कर दिया जाएगा।

ट्रेन संख्या 02187 रीवा-सीएसएमटी विशेष को दिनांक 23.04.2026 से निरस्त कर दिया जाएगा ।

उक्त नियमित ट्रेन सेवाओं का विवरण इस प्रकार है।

ट्रेन संख्या 20153 दिनांक 24.04.2026 से प्रत्येक शुक्रवार को 13:30 बजे सीएसएमटी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 09:45 बजे रीवा पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 20154 दिनांक 23.04.2026 से प्रत्येक गुरुवार को 15:50 बजे रीवा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:20 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी। यात्रा के दौरान ट्रेन दादर, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना।

मुंबई में ऑटिज्म जागरूकता को बढ़ावा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

रिस्प्लाइस ऑटिज्म रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ऑटिज्म के बढ़ते मामलों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. चंद्रशेखर थोडुपुनुरी ने कहा कि ऑटिज्म की शुरुआत गर्भ से ही हो जाती है, इसलिए समय रहते पहचान और नियंत्रण बेहद जरूरी है। फाउंडेशन, शिवसेना मेडिकल हेल्प सेल, माझा सु संकल्प अभियान और करुणा सेवा ट्रस्ट के सहयोग से 26 अप्रैल 2026 को माटुंगा (पूर्व) स्थित मैसूर ऑडिटोरियम में निःशुल्क गट हेल्थ असेसमेंट और माइक्रोबायोम टेस्टिंग कैंप आयोजित करेगा। फाउंडेशन का दावा है कि यह भारत का पहला संस्थान है, जो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन (FMT) थेरेपी प्रदान करता है। यह उपचार गट-ब्रेन एक्सिस को सुधारने पर आधारित है, जिससे ऑटिस्टिक बच्चों में सुधार देखा गया है। डॉ. थोडुपुनुरी के अनुसार, इस थेरेपी से 30-40 प्रतिशत तक लाभ और नई तकनीकों से 70-80 प्रतिशत रिकवरी की संभावना सामने आई है। उन्होंने बताया कि ऑटिज्म के मामलों में वृद्धि एक वैश्विक चिंता है और इसके पीछे एग्रोकेमिकल्स का शरीर में जमाव (बायोएक्यूम्यूलेशन) एक संभावित कारण हो सकता है। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के मस्तिष्क विकास को प्रभावित कर सकता है। फाउंडेशन ने आईसीएमआर में एक शोध भी पंजीकृत किया है और देशभर में गट हेल्थ डेटा एकत्र करने का अभियान चला रहा है। इस पहल का उद्देश्य नीतिगत स्तर पर बदलाव लाना और ऑटिज्म की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है। आयोजकों ने अभिभावकों से इस निःशुल्क कैंप का लाभ उठाने की अपील की है।

निःशुल्क गट हेल्थ कैंप 26 अप्रैल को
गट-ब्रेन एक्सिस आधारित उपचार पर जोर
विशेषज्ञों ने शुरुआती पहचान को बताया जरूरी

चालीसगांव रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर को मिली मंजूरी

263.86 करोड़ की परियोजना से बढ़ेगी क्षमता,
घटेगी ट्रेनों की देरी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में मध्य रेल के अंतर्गत आने वाली चालीसगांव रेल-ओवर-रेल (आरओआर) फ्लाईओवर परियोजना को 263.86 करोड़ की लागत से मंजूरी दे दी है। चालीसगांव क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही परिचालन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भीड़भाड़ से मिलेगी राहत

फिलहाल इस रेल खंड पर तीन लाइनों के बीच कई क्रॉसिंग होने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होती है, खासकर धुले की ओर से आने वाली ट्रेनों को व्यस्त मेन लाइन को पार करना पड़ता है। प्रस्तावित फ्लाईओवर ट्रेनों के मार्ग को अलग करेगा, जिससे ट्रैफिक जाम और देरी की समस्या काफी हद तक कम होगी।

भविष्य की बढ़ती मांग के लिए तैयारी

इस सेक्शन की वर्तमान लाइन क्षमता 45 .4% है, जो 2029-30 तक बढ़कर 107 .96% तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यह परियोजना भविष्य की बढ़ती यातायात मांग को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी।

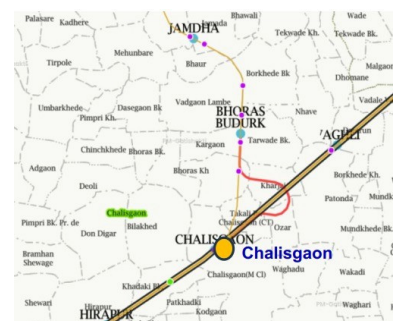

औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से क्षेत्र के चीनी, सीमेंट और अन्य उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही प्रतिवर्ष लगभग 0 .6 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। यह पहल रेलवे के नेटवर्क को आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

करीब 11 .01 किमी लंबी इस परियोजना का सर्वे कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसमें दो स्टेशन भवन, एक प्रमुख पुल, 16 छोटे पुल, एक अंडरब्रिज और पांच सबवे का निर्माण शामिल है। यह ट्रैक 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

समय की बचत और बेहतर कनेक्टिविटी

परियोजना के पूरा होने पर अप दिशा में लगभग 15 मिनट और डाउन दिशा में करीब 20 मिनट की समय बचत होगी। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई को भी सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही चालीसगांव और जामदा के बीच के खंड पर दबाव कम होगा।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

प्रियंका जैन
97699 94439

मेष नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामजिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। सुख के साधन जुटेंगे। नौकरी में वर्चस्व स्थापित होगा। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। निवेश शुभ रहेगा।

वृष यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। बगैर मांगे किसी को सलाह न दें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। धनार्जन होगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। अज्ञात भय व चिंता रहेंगे।

मिथुन अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। व्यवस्था नहीं होने से परेशानी रहेगी। व्यवसाय में कमी होगी। नौकरी में नोकझोंक हो सकती है। पार्टनरों से मतभेद हो सकते हैं। थकान महसूस होगी। अपेक्षित कार्यों में विघ्न आएंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। आय में निश्चितता रहेगी।

कर्क जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। जुए, सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। निवेश शुभ रहेगा।

सिंह पूजा-पाठ व सत्संग में मन लगेगा। आत्मशांति रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। मातहतों का सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

कन्या स्थायी संपत्ति की खरीद-फरोख्त से बड़ा लाभ हो सकता है। प्रतिद्वंद्विता रहेगी। पार्टनरों का सहयोग समय पर मिलने से प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय ठीक-ठीक चलेगा। आय में वृद्धि होगी। चोट व रोग से बाधा संभव है।

तुला मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल रहेगी। जीवनसाथी पर आपसी मेहरबानी रहेगी। जल्दबाजी में धनहानि हो सकती है। व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में सुकून रहेगा। निवेश लाभप्रद रहेगा। कार्य बनेंगे।

वृश्चिक क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। विवाद को बढ़ावा न दें। पुराना रोग बाधा का कारण रहेगा। स्वास्थ्य पर खर्च होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। छोटी सी गलती से समस्या बढ़ सकती है। व्यवसाय ठीक चलेगा।

धनु पार्टी व पिकनिक की योजना बनेगी। मित्रों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें।

मकर घर-बाहर अशांति रहेगी। कार्य में रुकावट होगी। आय में कमी तथा नौकरी में कार्यभार रहेगा। बेवजह लोगों से कहासुनी हो सकती है। दुःखद समाचार मिलने से नकारात्मकता बढ़ेगी। व्यवसाय से संतुष्टि नहीं रहेगी। पार्टनरों से मतभेद हो सकते हैं।

कुंभ दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। व्यवसाय में जल्दबाजी से काम न करें। चोट व दुर्घटना से बचें। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। घर-बाहर स्थिति मनोनुकूल रहेगी।

मीन प्रयास सफल रहेंगे। किसी बड़े कार्य की समस्याएं दूर होंगी। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। कर्ज में कमी होगी। संतुष्टि रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार मनोनुकूल चलेगा। अपना प्रभाव बढ़ा पाएंगे। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। जोखिम व जमानत के कार्य न करें।

नए घर में शुभ ऊर्जा और समृद्धि के लिए आवश्यक विधियां

प्रियंका जैन
97699 94439

गृहप्रवेश भारतीय संस्कृति में केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं माना जाता, बल्कि इसे जीवन के एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से नए घर में प्रवेश किया जाता है, उसी प्रकार उस घर की ऊर्जा, वातावरण और भविष्य का प्रभाव निर्धारित होता है। इसलिए गृहप्रवेश के समय अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। हिंदू परंपराओं के अनुसार गृहप्रवेश का शुभ समय, जिसे मुहूर्त कहा जाता है, दिन, तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रह-स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सही मुहूर्त में किया गया गृहप्रवेश घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और निवासियों के जीवन में स्थिरता तथा खुशहाली लाता है। इसलिए सामान्यतः गृहप्रवेश किसी अनुभवी पंडित या ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त निकलवाकर ही किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की ज्योतिषीय बाधा न रहे।

गृहप्रवेश के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया वास्तु पूजा की मानी जाती है। इसमें घर के वास्तु पुरुष की विधिवत पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है, जिससे घर में संतुलित ऊर्जा बनी रहती है। यह माना जाता है कि वास्तु दोष दूर करने और सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए यह पूजा आवश्यक है।

घर में प्रवेश करते समय पांव रखने की दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है। परंपरा के अनुसार यदि घर का मुखिया पुरुष हो तो उसे दाहिना पांव पहले रखना चाहिए और यदि महिला हो तो बायां पांव पहले रखना शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया को शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जिससे जीवन में सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। गृहप्रवेश के दौरान कुछ मांगलिक वस्तुएं साथ ले जाना भी शुभ माना जाता है। इनमें अनाज, धन, मिष्ठान, जल से भरा कलश और नारियल प्रमुख होते हैं। ऐसा विश्वास है कि इन वस्तुओं के साथ प्रवेश करने से घर में कभी अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती। जल और नारियल को पवित्रता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।

घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद पूजा स्थल की स्थापना भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष रूप से ईशान कोण को पूजा के लिए सबसे शुभ स्थान माना जाता है। यहां भगवान गणेश की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता माना जाता है। इसके बाद रसोई घर में अग्नि पूजन करने की परंपरा भी प्रचलित है, जो घर की ऊर्जा और भोजन की पवित्रता को दर्शाता है। कुछ परंपराओं में कन्या पूजन और गो पूजन को भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह माना जाता है कि कन्या और गाय में देवी का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि इन पूजाओं से परिवार में शांति और संतुलन बना रहता है। रसोई घर का गृहप्रवेश में विशेष महत्व होता है। पहली बार रसोई में दूध उबालने की परंपरा है, जिसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मिष्ठान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिससे घर में मीठा और सुखद जीवन आरंभ होने की मान्यता है। गृहप्रवेश में मंगल कलश का भी विशेष स्थान होता है। कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखा जाता है।

महिला आरक्षण : विवादित टिप्पणी कर फंसे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद

महिला आयोग को जवाब देंगे पप्पू यादव

- राज्य महिला आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए दी तीन दिन की मोहलत
- संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लोस अध्यक्ष से की जाएगी सिफारिश

एजेंसी । पटना

महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विवादित बयान देने के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राजनीतिक और कानूनी घेरे में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनके बयान की तीखी आलोचना की है, वहीं बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तीन दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है।

90 फीसद महिलाएं बिना प्रभावशाली....

विवाद उस बयान से जुड़ा है, जिसमें यादव ने दावा किया कि "राजनीति में 90 प्रतिशत महिलाएं बिना प्रभावशाली नेताओं के संपर्क के आगे नहीं बढ़ पातीं।" इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "75 प्रतिशत नेता अश्लील सामग्री देखते हैं" और व्यवस्था को महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बयान को "चौंकाने वाला" बताते हुए कहा कि यह नारी सशक्तिकरण के प्रयासों के विपरीत है। पार्टी के अन्य नेता तुहिन सिन्हा ने इसे "घृणित और शर्मनाक" करार देते हुए विपक्षी दलों से स्पष्ट रुख की मांग की। विवाद बढ़ने के बीच पप्पू यादव ने नोटिस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, बल्कि शोषण की वास्तविकता को उजागर किया है।

सामाजिक असामनता का मुद्दा उठाया

सांसद ने अपने बयान में सामाजिक असमानता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों की भागीदारी उद्योग, न्यायपालिका, मीडिया स्वामित्व और धार्मिक ट्रस्टों में नगण्य है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए।

फिलहाल, महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए इस तरह के बयान से न केवल राजनीतिक विवाद गहराता है, बल्कि संसद और सार्वजनिक विमर्श में भाषा की मर्यादा पर भी सवाल खड़े होते हैं।

पहलगाम हमला पहली बरसी पर छलका दर्द

एजेंसी । कानपुर

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीड़ित परिवारों ने न्याय और सम्मान की मांग दोहराई है। हमले में मारे गए 26 लोगों के परिजनों ने सभी मृतकों को 'शहीद' घोषित करने की मांग उठाई है। श्यामनगर निवासी कारोबारी शुभम द्विवेदी (आयु 30 वर्ष) की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि उनके पति की हत्या उनके सामने की गई और यह घटना जीवनभर का आघात है। उन्होंने बताया कि हमले में कुल 26 लोगों की उनके परिजनों के सामने गोली मारकर हत्या की गई थी। आधिकारिक विवरण के अनुसार, हमलावरों ने पर्यटकों की पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया, जिससे यह घटना एक लक्षित आतंकी हमला मानी गई। मृतकों में विभिन्न राज्यों के पर्यटक शामिल थे, जिनमें उत्तर प्रदेश से भी कई लोग थे। परिवार के मुताबिक, शुभम द्विवेदी का जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था और उनकी शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी के महज 68 दिन बाद 22 अप्रैल को यह हमला हुआ।

अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़, यूपी-बिहार से चार गिरफ्तार

- फर्जी API और टेलीग्राम बॉट के जरिए डेटा की तस्करी

एजेंसी । मुजफ्फरपुर

बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरपुर से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग-अलग जिलों से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय नागरिकों की संवेदनशील जानकारी विदेशी अपराधियों तक पहुंचा रहे थे। पुलिस के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 को केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया। जांच में अहियापुर थाना क्षेत्र के रिषभ कुमार के घर से अवैध डेटा एक्सचेंज नेटवर्क संचालित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसटीएफ, साइबर थाना और जिला आसूचना इकाई की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग

ऋषभ कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने तीन अन्य सहयोगियों—दीपक चौधरी उर्फ आशु कुमार (गाजीपुर, यूपी), सुधांशु कुमार (दरभंगा, बिहार) और साहिल कुमार (मुजफ्फरपुर, बिहार)—को भी दबोच लिया। प्रारंभिक जांच में गिरोह के तार कई राज्यों और विदेशी नेटवर्क से जुड़े मिले हैं। जांच में सामने आया है कि गिरोह फर्जी API, एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल और बॉट्स के माध्यम से आधार, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और अन्य निजी सूचनाएं इकट्ठा कर उन्हें विदेशी साइबर अपराधियों को बेचता था।

फॉरेंसिक जांच से खुलेंगे और राज

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बरामद मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय लिंक का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बैंक विवरण, ओटीपी, आधार जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। एक छोटी सी लापरवाही बड़े साइबर अपराध का कारण बन सकती है।

खड़गे की टिप्पणी से करोड़ों जनभावनाएं आहत: साय

एजेंसी । रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे "लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध" बताते हुए सार्वजनिक जीवन में भाषा के स्तर पर गंभीर चिंता जताई। मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि इस तरह की टिप्पणी न केवल प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उन करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को भी आहत करती है जो देश के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की गरिमा पर "सीधा आघात" करार दिया। राजनीतिक परिदृश्य के आंकड़ों के अनुसार, देश में 90 करोड़ से अधिक मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

साय ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना

साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकार की भाषा पार्टी की "राजनीतिक हताशा" को दर्शाती है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से प्रधानमंत्री और जनता से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम चुनावों से पहले इस तरह के बयानबाजी से सियासी ध्रुवीकरण तेज हो सकता है और मुद्दों से ध्यान भटकने की आशंका रहती है।

महिला आरक्षण पर बसपा अपने स्टैंड पर अडिग: मायावती

एजेंसी । लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन सुदृढ़ करने और जनाधार विस्तार के लिए सक्रिय अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी 15 अप्रैल को घोषित अपने रुख पर कायम है।

जन-जन तक पहुंचाएं बसपा के कार्य

मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे बसपा शासनकाल में किए गए विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाएं। पार्टी के दावों के अनुसार, राज्य में बने कई एक्सप्रेस-वे और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा जैसी परियोजनाओं की प्रारंभिक योजना बसपा सरकार के दौरान तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में "कानून द्वारा कानून का राज" और "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की नीति के माध्यम से ही व्यापक विकास और बेहतर कानून व्यवस्था संभव है।

अनुशासन बनाते हुए धरना-प्रदर्शन से बचें

महिला आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी लाइन स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को सार्वजनिक किए गए रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही निर्देश दिया गया कि इस विषय पर कार्यकर्ता बैठकों में पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन अनुशासन के तहत किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन से बचें।

केदारनाथ धाम के कपाट खुले श्रद्धालुओं का लगा तांता

एजेंसी । देहरादून

ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार प्रातः 8 बजे कपाट खुलते ही "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 5 बजे शुरू हुई और प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न कराई गई। उद्घाटन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित उपस्थित रहे। मंदिर परिसर को इस वर्ष 51 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया, जबकि कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

2025 में आए थे दस लाख श्रद्धालु

चारधाम यात्रा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, हर वर्ष लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। वर्ष 2025 में यात्रा के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि 2026 में इस संख्या के और बढ़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से श्रद्धालुओं के प्रति सेवा और आतिथ्य भाव बनाए रखने की अपील की।

बंद कमरे में मिले पीके और तेजप्रताप

एजेंसी । पटना

बिहार की राजनीति में हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य में करीब दो दशक तक सत्ता में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सम्राट चौधरी को नेतृत्व सौंपे जाने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है।

अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट का दर्जा

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शेखा झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (रामसर साइट) का दर्जा मिल गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 99 और उत्तर प्रदेश में 12 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि को राज्य के पर्यावरणीय प्रयासों की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि इससे पारिस्थितिकी संतुलन मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि राज्य सरकार जैव विविधता

संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रामसर दर्जा मिलने से आर्द्रभूमि संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संवर्धन को संस्थागत समर्थन मिलता है।

व्यापार जगत

ऑटो-डेबिट पर 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट

- ईएमआई की कटौती को लेकर RBI ने लागू किए नए नियम

एजेंसी । नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग में पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटो-डेबिट सिस्टम को लेकर कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नए नियमों के तहत अब किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था को EMI, बीमा प्रीमियम या 24 घंटे पहले ग्राहक को पूर्व सूचना अनिवार्य होगा।

ग्राहकों का ट्रांजैक्शन पर नियंत्रण

नए नियमों से ग्राहकों को अपने बैंक खाते से होने वाली स्वचालित कटौतियों पर सीधा नियंत्रण मिलेगा। अलर्ट प्राप्त होने के बाद ग्राहक निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान को मंजूरी दे सकते हैं।

उल्लंघन पर शिकायत का प्रावधान

यदि कोई बैंक या सेवा प्रदाता 24 घंटे पूर्व सूचना दिए बिना ऑटो-डेबिट करता है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। RBI ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। RBI का यह कदम बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने और ग्राहकों को वित्तीय जोखिम से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ब्रेंट 98 डॉलर प्रति बैरल के करीब

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति (Supply) को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। बुधवार सुबह शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड लगभग 98 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) करीब 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना रहा। पिछले दो कारोबारी सत्रों में ब्रेंट क्रूड में करीब 10% की तेजी दर्ज की गई है, जो सप्लाई जोखिम और बाजार में बढ़ती चिंता को दर्शाती है।

सेंसेक्स 767 अंक फिसला, निफ्टी 24,400 के नीचे

- ग्लोबल संकेतों के दबाव में बाजार

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट दर्ज की गई। ईरान द्वारा प्रस्तावित शांति वार्ता के दूसरे दौर को खारिज किए जाने की खबर के बाद निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ी, जिससे बाजार में व्यापक बिकवाली देखने को मिली। दिन की शुरुआत में सेंसेक्स 253.99 अंक गिरकर 79,019.34 पर और निफ्टी 105.75 अंक टूटकर 24,470.85 पर खुला था।

बाजार की चौड़ाई लगभग संतुलित

शुरुआती कारोबार में कुल 2,708 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें 1,366 शेयर बढ़त (गैनर्स) और 1,342 शेयर गिरावट (लूजर्स) के साथ कारोबार कर रहे थे—जो बाजार की मिश्रित लेकिन दबावयुक्त स्थिति को दर्शाता है। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर लाल निशान में रहे, जबकि निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखा गया। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस में 1.28% से लेकर 8.69% तक की गिरावट दर्ज की गई।

पिछले सत्र में रही तेजी

मंगलवार को बाजार में मजबूती रही थी। सेंसेक्स 753.03 अंक (0.96%) चढ़कर 79,273.33 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 211.75 अंक (0.87%) उछलकर 24,576.60 पर बंद हुआ था। वैश्विक अनिश्चितता, विशेषकर पश्चिम एशिया की स्थिति, निकट अवधि में बाजार की दिशा तय करेगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की गतिविधि और डॉलर इंडेक्स की चाल भी बाजार पर असर डाल सकती है। फिलहाल निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, जिससे उतार-चढ़ाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

सोने में हल्की गिरावट, चांदी 10,000 रुपये टूटी

एजेंसी । नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में तेज गिरावट देखने को मिली। देशभर के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,55,270 रुपये से 1,55,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार करता रहा, वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,330 रुपये से 1,42,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना रहा। चांदी की कीमत में एक दिन में करीब 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जिससे

दिल्ली सर्राफा बाजार में इसका भाव घटकर 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,55,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जबकि मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,55,270 रुपये और 22 कैरेट 1,42,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा।

वस्त्र निर्यात में 2.1% का इजाफा

- FY26 में 3.16 लाख करोड़ का हुआ वस्त्र निर्यात

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के वस्त्र क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में संतुलित वृद्धि दर्ज की है। हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र निर्यात 3,09,859.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,16,334.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 2.1% की वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रदर्शन प्रमुख बाजारों में स्थिर मांग और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है।

मैन-मेड टेक्सटाइल्स और हस्तशिल्प की मांग

मानव निर्मित फाइबर (MMF) आधारित उत्पादों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां निर्यात 41,196.0 करोड़ रुपये से बढ़कर 42,687.8 करोड़ रुपये हो गया, यानी 3.6% की वृद्धि। मूल्यवर्धित खंडों में हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर हस्तशिल्प ने 6.1% की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की और यह 14,945.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,855.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

यूएई समेत 120+ बाजारों में विस्तार

अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 120 से अधिक निर्यात गंतव्यों में वृद्धि दर्ज की गई, जो भौगोलिक विविधीकरण का संकेत है। प्रमुख बाजारों में यूएई (22.3%), यूके (7.8%), जर्मनी (9.9%), स्पेन (15.5%), जापान (20.6%), मिस्र (38.3%), नाइजीरिया (21.4%), सेनेगल (54.4%) और सूडान (205.6%) में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। मूल्यवर्धित खंडों में हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर हस्तशिल्प ने 6.1% की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की।

MCX: सोना 1,479 और चांदी 3,885 चढ़ी

एजेंसी । नई दिल्ली

कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज MCX पर बुधवार को बुलियन में मजबूती के साथ ऊंचा कारोबार दर्ज हुआ। कुल टर्नओवर 1,54,721.67 करोड़ रुपये रहा, जिसमें वायदा (Futures) सेगमेंट में 20,902.72 करोड़ रुपये और ऑप्शंस में 1,33,818.51 करोड़ रुपये का नॉशनल कारोबार शामिल रहा। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13,369.77 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जबकि बुलियन इंडेक्स 'बुलडेक्स' फ्यूचर्स 131 अंक बढ़कर 36,894 पर पहुंच गया। सोना वायदा में मजबूती का

रुख बना रहा। MCX गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट 1,479 रुपये यानी 0.98% की बढ़त के साथ 1,53,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा, जबकि दिन के दौरान इसने 1,53,699 रुपये का उच्च और 1,53,001 रुपये का निचला स्तर छुआ। नैचुरल गैस वायदा भी 3.2 रुपये यानी 1.27% चढ़कर 255.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर पहुंच गया।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

महानगरपालिका की सामान्य मासिक बैठक **सोमवार, दिनांक 4 मई 2026 को दोपहर 2:00 बजे**, महानगरपालिका के मुख्य कार्यालय में निम्नलिखित कार्यों पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

१–४. (१) उपनगरीय रेलवे यात्री सलाहकार समिति, मध्य रेलवे, मुंबई पर महानगरपालिका के एक प्रतिनिधि का;
(२) छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय के न्यासी मंडल पर महानगरपालिका के दो प्रतिनिधियों का;
(३) द चिल्ड्रन्स एड सोसायटी, मुंबई की संचालन परिषद पर दो सदस्यों का; तथा
(४) उपनगरीय रेलवे यात्री सलाहकार समिति, पश्चिम रेलवे, मुंबई पर महानगरपालिका के एक प्रतिनिधि का नामनिर्देशन करना।

५. प्रश्नोत्तर।

६. प्रस्तावों की सूचनाओं पर विचार करने के लिए बैठक की तिथि निर्धारित करना।

स्थायी समिति के प्रस्ताव:-

७. भांडुप संकुल स्थित नियंत्रण कक्ष से निटी गेट तक ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा संबंधित उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना करना।
८. भांडुप संकुल स्थित 1910 एमएलडी (दैनिक क्षमता) पंपिंग स्टेशन के 4 पंपों की मुख्य मरम्मत एवं नवीनीकरण करना।
९. बृहन्मुंबई महानगरपालिका में जल आपूर्ति परियोजना विभाग हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य करने के लिए स्थापित विशेष भू-अधिग्रहण कक्ष तथा इस कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सेवा को अस्थायी रूप से आगे जारी रखना।
१०. भांडुप संकुल स्थित जल पूर्व-प्रक्रिया संयंत्र से संबंधित कार्य सहित ट्रसेस बदलना।
११. 'एल' विभाग के संघर्ष नगर पंपिंग स्टेशन में पंपिंग सेट बदलना तथा अन्य संबंधित कार्य करना।
१२. मुंबई 3A पंपिंग स्टेशन, पांजरापुर में केबीएल निर्मित हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप (24 यूपीएच) के लिए संपूर्ण रोटेटिंग असेंबली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू करना।
१३. वेरावली जलाशय समूह में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का विस्तार एवं सुधार करना।
१४–१५. (१४) 'जी/दक्षिण'; तथा (१५) 'एफ/दक्षिण' विभाग में पानी के रिसाव को रोकना, दूषितीकरण को रोकना तथा अन्य संबंधित कार्य करना।
१६. पश्चिम उपनगरों के विभिन्न स्थानों पर जलापूर्ति में सुधार करने हेतु विभिन्न व्यास की जलवाहिनियों की आपूर्ति, बिछाना, बदलना तथा अन्य संबंधित कार्य करना।
१७. कार्यकारी अभियंता परिवहन (शहर) कार्यालय की स्थापना पर नियुक्त विवक्षित वाहनचालक का महानगरपालिका की सेवा में नियुक्ति की तिथि से छह महीने पूर्ण होने से पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण करने की शर्त में शिथिलता प्रदान करना।
१८. कार्यकारी अभियंता (परिवहन) पा. पु. म. नि. उपविभाग के अंतर्गत विभिन्न यानगृहों के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों एवं यंत्रसामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं संचालन करना।

'बेस्ट' समिति के प्रस्ताव:-

१९. 'बेस्ट' के मोडमाल का निपटान करना।
२०. 'बेस्ट' उपक्रम में अस्थायी नवघाणी, श्रेणी पी१/ टी१ संवर्ग के विवक्षित पदों को आगे जारी रखना।
२१. विद्युत आपूर्ति शाखा के सहायक स्थापना के परिविक्षाधीन अभियंताओं के अस्थायी पदों का सृजन करना।

आयुक्त एवं अन्य से प्राप्त पत्रव्यवहार:-

२२. महानगरपालिका उप आयुक्त को अधिकारों का प्रत्यायोजन करना।
२३. 'ई' विभाग के माझगांव स्थित सर्वे क्र. ५६५, १/५६५, १९/५६५ एवं १बी/५६५ धारित 'वनस्पति उद्यान' इस सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आरक्षित भूमि का अधिग्रहण करना।
२४. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अधीन विद्यालयों को, सार्वजनिक जन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 'निजी संस्थाओं के शिक्षकों सहित संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन (FSMPT)' इस संशोधित नीति के अनुसार निजी संस्थाओं को संचालन हेतु देना।
२५. 'एच/पश्चिम' विभाग के बांद्रा (पश्चिम) गांव के अंतिम भूखंड क्र. ७९, ८० सी (भाग), ९९ (भाग), १०० एवं १०१, नगर रचना योजना क्र. बांद्रा तीन, खारी गांव धारित 'खेल का मैदान' इस सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आरक्षित भूमि का अधिग्रहण करना।
२६. 'डी' विभाग के चिरंजी लाल लोयलका मार्ग (सीरी रोड) स्थित कमला नेहरू पार्क के नामनिर्दिष्ट मनोरंजन मैदान / कमला नेहरू पार्क इस निर्धारित आरक्षण हेतु भूमि का सार्वजनिक हित में सड़क निर्माण एवं उपयोग की अनुमति देना।
२७. महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर रचना अधिनियम, १९६६ के अंतर्गत प्रस्तावित, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन एवं पुनर्स्थापना करते समय उचित मुआवजा प्राप्त करने तथा पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा १९ के अनुसार अधिसूचना प्रकाशित की गई भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में तथा भविष्य में होने वाले भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में अधिग्रहित भूमि को भारमुक्त करके महानगरपालिका को हस्तांतरित करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष आग्रह रखने की बात को नीति के रूप में स्वीकार करना।
२८. बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा स्वयंटर स्टॉल धारकों के लाइसेंस के हस्तांतरण से संबंधित वर्तमान नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर रिपोर्ट।
२९. महानगरपालिका के दिनांक ४ मार्च १९६८ के ठराव क्रमांक १८९७ के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण सूची में अनुक्रमांक MS/१३, भूखंड क्रमांक ९३ (पै), सर्वे क्रमांक १०९७ (पै), मौजे मुलुंड (पूर्व) स्थित भूखंड के भूमि अधिग्रहण की बाब को निरस्त करना।
३०. बृहन्मुंबई महानगरपालिका में महानगरपालिका सदस्यों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज करना।
३१–४७. (३१) कांदिवली (पूर्व) स्थित लोखंडवाला फाउंडेशन स्कूल से सफारा हाइट्स टॉवर की ओर जाने वाला तथा अनिता नगर ११ की ओर जाने वाला मार्ग जहां परस्पर मिलते हैं, वहां बनने वाले अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक' रखना; (३२) 'के/पूर्व' विभाग के विलेपार्ले (पूर्व) स्थित प्रभाग क्रमांक ८४ में शिरोडकर अस्पताल के सामने स्थित चौराहे का नाम 'मंगलाबाई भागवत चौक' रखना; (३३) कांदिवली (पूर्व), प्रभाग क्रमांक २७ में लोखंडवाला स्थित विश्वकर्मा चौक से सावित्रीबाई फुले मैदान की ओर जाने वाले मार्ग पर, ग्रीन हिल्स इमारत क्रमांक १ के पास अनुदत्त विद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग के पास बनने वाले अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'तथागत गौतम बुद्ध चौक' रखना; (३४-३५) 'एच/पूर्व' विभाग के वांद्रे (पूर्व), प्रभाग क्रमांक ९२ स्थित भारत नगर में भारत नगर मुख्य मार्ग तथा (३४) बी. के. सी. मुख्य मार्ग जहां परस्पर मिलते हैं वहां बनने वाले अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'इमाम जियाउल कदीर अंसारी चौक' तथा (३५) चाली मार्ग जहां परस्पर मिलते हैं वहां बनने वाले अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'इमरान अहमद शेख चौक' रखना; (३६) मालाड (पूर्व) स्थित प्रभाग क्रमांक ३६ में रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने वाला दत्त मंदिर मार्ग, आगे पश्चिमी द्रुतगति महामार्ग से जहां मिलता है वहां बनने वाले अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर चौक' रखना; (३७) सांताक्रूज (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्रमांक ७१ में सुनिल दत्त उद्यान मार्ग तथा हिराबुवा गावडे मार्ग जहां एक-दूसरे को काटते हैं वहां बनने वाले चौराहे का नाम 'श्री तारेश देव चौक' रखना; (३८) विलेपार्ले (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्रमांक ७१ में सेंट ब्राज मार्ग तथा सेंट फ्रांसिस क्रॉस मार्ग जहां एक-दूसरे को काटते हैं वहां बनने वाले चौराहे का नाम 'जोसेफ बाप्टिस्टा (काका बाप्टिस्टा) चौक' रखना; (३९-४०) 'एस' विभाग के प्रभाग क्रमांक १२२ में पवई गांव स्थित हिरानंदानी फाउंडेशन के (३९) स्कूल के सामने स्थित सर्वे क्रमांक १३/डी वाले उद्यान का नाम 'श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान' रखना; और (४०) स्कूल के पास स्थित सर्वे क्र. १३अ/१/२ धारित खेल के मैदान का नाम 'पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मैदान' रखना; (४१) 'सी' विभाग के प्रभाग क्र. २२१ में कालबादेवी रोड और मुंबादेवी मार्ग जहां एकत्र होते हैं, वहां बनने वाले अंग्रेजी 'वाई' आकार के चौराहे का नाम 'परमपूज्य प्रन्यास प्रवर श्रीमद भाद्रानंद विजयजी गणिवर महाराज चौक' रखना; (४२) अंधेरी (पूर्व) स्थित अंधेरी रेलवे स्टेशन के समीप साईनगर, ना. सी. फडके मार्ग पर वर्तमान में पूर्ण हुए उड्डाणपुल का नाम 'कार्यसम्राट आमदार रमेश लटके उड्डाणपुल' रखना; (४३) 'पी/दक्षिण' विभाग के गोरेगांव (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्र. ५६ में उन्नत नगर मार्ग क्र. २, नए यातायात पुलिस कार्यालय के पास स्थित चौराहे का नाम 'माजी नगरसेवक कृष्णनाथ रामचंद्र नेवरेकर चौक' रखना; (४४-४५) बोरीवली (पश्चिम), प्रभाग क्रमांक १७ में (४४) चिकुवाड़ी स्थित हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मैदान के सामने कांती पार्क से फिनिक्स हॉस्पिटल तक के समानांतर मार्ग का नाम 'महादेव तुकाराम भंडारी मार्ग' तथा (४५) साईबाबा नगर में साईबाबा मेन रोड से साईबाबा मंदिर क्रॉसरोड पर, केरकर जिमखाना के सामने बने अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'भारतीय विकास संस्थान चौक' रखना; (४६) 'पी/दक्षिण' विभाग के गोरेगांव (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्रमांक ५६ में महात्मा गांधी मार्ग और बझमे इतेमाद मार्ग पर बने अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'गोरेगांवचा ओंकारेश्वर चौक' रखना; (४७) 'एफ/उत्तर' विभाग के प्रभाग क्रमांक १७८ में डेविड बैरेटो मार्ग से पृथ्वेश ट्यूटोरियल्स तक जाने वाले मार्ग क्र. ३२ का नाम 'देविका रॉय मार्ग' रखना।
४८. महानगरपालिका की सभी वैधानिक समितियों, प्रभाग समितियों तथा विशेष समितियों की बैठकों की शुरुआत में 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीत का गायन करना।
४९–६१. (४९) बोरीवली (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्र. १७ में चिकुवाड़ी क्षेत्र में सत्व होटल से वृशाली इमारत तथा जानुविला बंगला से आदित्य सोसायटी के कोने पर बने चौराहे का नाम 'भूमिपुत्र यशवंत भास्कर भंडारी चौक' रखना; (५०) अंधेरी (पूर्व) स्थित प्रभाग क्रमांक ७५ में डिलाइट बेकरी, मरोल मरॉशी रोड के चौराहे का नाम 'सहकार महर्षि लोकनेता राजाराम बापू पाटील चौक' रखना; (५१–५३) 'पी/दक्षिण' विभाग के अंतर्गत; (५१) मालाड (पश्चिम), प्रभाग क्र. ५० में आकांक्षा सोसायटी के पास वासरी हिल स्थित खेल के मैदान का नाम 'श्री गजानन महाराज खेल का मैदान' रखना; (५२) गोरेगांव (पश्चिम), प्रभाग क्र. ५० में गांव पहाड़ी गोरेगांव स्थित अनमोल टॉवर के पास मनोरंजन मैदान का नाम 'श्री स्वामी नारायण महाराज मनोरंजन मैदान' रखना; तथा (५३) मौजे मालाड (दक्षिण), मालाड (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्र. ५० में शक्ति मोटर्स के सामने, लिंक रोड पर स्थित मनोरंजन मैदान का नाम 'श्री स्वामी काडसिद्धेश्वर महाराज मनोरंजन मैदान' रखना; (५४) 'आर/उत्तर' विभाग के दहिसर (पूर्व) में विद्यामंदिर स्कूल के सामने, छत्रपति शिवाजी रोड स्थित खेल के मैदान का नाम 'डॉ. अशोक मुलगांवकर खेल का मैदान' रखना; (५५) 'पी/दक्षिण' विभाग के मालाड गांव, गोरेगांव (पश्चिम) स्थित प्रभाग क्र. ५० में निर्माण इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, लिंक रोड स्थित मनोरंजन मैदान का नाम 'श्री प्रमुख स्वामी महाराज मनोरंजन मैदान' रखना; (५६) 'एम/पूर्व' विभाग के मौजे देवनार, गोवंडी स्थित रोड नं. १ व २, ९० फुट रोड नाले के पास, रफीकनगर महानगरपालिका स्कूल के समीप स्थित खेल के मैदान का नाम 'पीर बाबा बद्धुद्दीन हुसैनी दरगाह (पेण) मैदान' रखना; (५७) 'जी/उत्तर' विभाग के प्रभाग क्र. १८९ में क्षेत्रपालेश्वर सोसायटी के सामने स्थित जस्मीन मिल मार्ग इस सड़क को ६० फुट छेद मार्ग जहां काटता है, वहां बने अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'चंद्रकांत रामचंद्र नाईक चौक' रखना; (५८–५९) 'पी/दक्षिण' विभाग के गोरेगांव (पश्चिम) स्थित वॉर्ड क्र. ५० के बांगुर नगर क्षेत्र में; (५८) कावेरी महिमा सोसायटी से नंदधाम ब्रिजधाम सोसायटी तक के मार्ग का नाम 'नवल किशोर गोयनका मार्ग' तथा (५९) महाराज अग्रसेन मार्ग और नंदधाम ब्रिजधाम सोसायटी के पास बने अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'सुमत जाजू चौक' रखना; (६०) 'एफ/उत्तर' विभाग के प्रभाग क्र. १७७ में लेडी जहांगीर रोड तथा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने स्थित लखमसी नप्पू रोड जहां एक-दूसरे को काटते हैं, वहां बने चौराहे का नाम 'गायनाचार्य पंडित नारायणराव व्यास चौक' रखना; तथा (६१) 'एच/पश्चिम' विभाग के प्रभाग क्र. १०२ में एस. वी. रोड, वांद्रे (पश्चिम) के ब्रिज के नीचे स्थित ट्रैफिक चौकी और फायर ब्रिगेड के सामने स्थित जंक्शन पर बने चौराहे का नाम 'प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता दिलीप कुमार (यूसुफ खान) चौक' रखना।
६२. 'बी' विभाग कार्यालय की सीमा में निशानपाड़ा रोड तथा सरदार वल्लभभाई पटेल रोड को जोड़ने वाले उमरखाड़ी क्रॉस रोड की ९.१५ मीटर चौड़ाई की नियमित सड़क रेखा निर्धारित करना।
६३–६४. (६३) प्रभाग क्र. ७३ में पश्चिमी द्रुतगति महामार्ग तथा जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड के जंक्शन पर स्थित चौराहे का नाम 'छत्रपति शिवाजी महाराज चौक'; तथा (६४) 'एम/पूर्व' विभाग के प्रभाग क्र. १३९ में शहीद अब्दुल हमीद मार्ग, जी. एम. लिंक रोड के उड्डाणपुल के नीचे स्थित जिजाबाई भोसले मार्ग जहां शिवाजी नगर जंक्शन पर एक-दूसरे को काटते हैं, वहां बनने वाले चौराहे का नाम 'हजरत शाह शराफत अली मियां (र.अ.) चौक' रखना।
६५. 'एस' विभाग के भांडुप (पूर्व) स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में नगर भूमापन क्र. ६६८ से ६७२, ६९६ से ७११, १०३३ से १०३९ को प्रभावित करने वाले विकास नियोजित मार्गों की ९.१५ मीटर चौड़ी नियमित सड़क रेखा निर्धारित करने का अधिकार आयुक्त को देना।
६६. 'के/पूर्व' विभाग के अंधेरी (पूर्व), कोंडीविटा, महेश्वरी नगर स्थित मनोरंजन मैदान का नाम 'विश्वशांति दूत सुनील दत्त मनोरंजन मैदान' रखना।
६७–६८. (६७) घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड के उड्डाणपुल का नाम 'भारतरत्न मौलाना आजाद उड्डाणपुल'; तथा (६८) प्रभाग क्र. १६९ में लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्थित द्विस्तरीय उड्डाणपुल का नाम 'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे उड्डाणपुल' रखने के संबंध में।
६९–७०. (६९) मानसिक रूप से मंद / विशेष बालक तथा उनके अभिभावक अथवा एक सहायक को 'बेस्ट' उपक्रम की बसों में यात्रा करते समय टिकट अथवा बस पास में ५० प्रतिशत; और (७०) 'बेस्ट' उपक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आजीवन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के संबंध में रिपोर्ट।
७१. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में लागू की जाने वाली सशुल्क पार्किंग योजना के अंतर्गत पार्किंग स्थलों के ठेके, निर्धारित आरक्षण के अनुसार, महिला बचत समूहों तथा शिक्षित बेरोजगार संस्थाओं को देने के संबंध में निर्धारित शर्तों में संशोधन करना।
७२. महानगरपालिका / 'बेस्ट' की स्वामित्व वाली इमारतों / भूमि पर दूरसंचार टावर / मनोरे स्थापित करने हेतु अनुमति / नियमितीकरण आदि के संबंध में नीति।
७३. सड़कों, पथों, गलियों तथा चौराहों आदि के नामकरण / पुनर्नामकरण के संबंध में नई एकीकृत नीति एवं कार्यप्रणाली को अपनाना।
७४. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के विशाल सभागृह में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करना।
७५. श्री सुधांशु मोहन द्विवेदी, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) की उप प्रमुख अभियंता (स्थापत्य) के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करना।
७६–७८. (७६) मालाड (पूर्व) स्थित प्रभाग क्र. ३६ में पश्चिमी द्रुतगति महामार्ग से प्रारंभ होकर भुयारी मार्ग की ओर जाने वाले दत्तमंदिर मार्ग को पुष्पा पार्क मार्ग क्र. ३ (क्लासिक होटल के पास) जहां काटता है, वहां बने अंग्रेजी 'टी' आकार के चौराहे का नाम 'प्रमुख स्वामी महाराज चौक' रखना; (७७) 'बी' विभाग के प्रभाग क्र. २२३ में सरदार वल्लभभाई पटेल रोड तथा केशवजी नाईक रोड (डोंगरी पेट्रोल पंप के पास) जहां एक-दूसरे को काटते हैं, वहां बनने वाले चौराहे का नाम 'सफदर एच. करमाली चौक' रखना; तथा (७८) 'डी' विभाग के भुलाभाई देसाई मार्ग स्थित सर्वे क्र. २/५९५ एवं ५/५९५, मलबार हिल क्षेत्र के टाटा उद्यान (भाग १ एवं २) के रूप में ज्ञात मनोरंजन मैदान का नाम 'सर रतन टाटा मनोरंजन मैदान' रखना।
७९. विशेष समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को स्थायी करना।

प्रस्ताव की जानकारियां :-

८०–८१. श्रीमती रीटा भ. मकवाना द्वारा (८०) बृहन्मुंबई महानगरपालिका की सीमा के अंतर्गत इमारतों के पुनर्विकास के दौरान भारी उपकरणों के दबाव से पारंपरिक जल स्रोतों (कुओं) का जल समाप्त न हो, इसके लिए पुनर्विकास परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व क्षेत्र की कुओं तथा भूजल स्तर का पूर्व सर्वेक्षण करना, गहरे उत्खनन एवं पाइलिंग वाले परियोजनाओं के लिए भूजल प्रभाव रिपोर्ट अनिवार्य करना आदि उपायों को विकासकर्ताओं के लिए अनिवार्य किया जाए; तथा **(८१)** बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा सड़कों के सीमेंट कंक्रीटीकरण के कार्य के दौरान 'बेस्ट' उपक्रम द्वारा पुराने विद्युत तारों के स्थान पर अधिक क्षमता वाले तार बिछाकर विद्युत उप-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाए।
८२. श्री ताजिंदरसिंह तिवाना द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मुंबई शहर के १८ से २५ आयु वर्ग के युवाओं को नागरी प्रशासन में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 'महापौर नेक्स्ट जेन सिविक फेलोज प्रोग्राम' इस पायलट परियोजना को लागू करना।
८३. श्रीमती शीतल सु. गंभीर द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अस्पतालों में संतान प्राप्ति में कठिनाई का सामना कर रहे तथा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने वाले दंपतियों को 'आईवीएफ' उपचार पद्धति की सुविधा अत्यंत कम दरों पर उपलब्ध कराई जाए।
८४. श्रीमती वर्षा स्व. टेंबवलकर द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका की सीमा में जल विभाग के माध्यम से पुरानी जलवाहिनियों के स्थान पर तथा नई बिछाई जाने वाली जलवाहिनियों में उन्नत तकनीक आधारित आधुनिक कैमरे स्थापित किए जाएं।
८५. श्रीमती शीतल सु. गंभीर द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अस्पतालों तक पहुंचने के लिए मरीजों हेतु 'निकटतम रेलवे स्टेशन से महानगरपालिका अस्पताल' तक 'बेस्ट' उपक्रम की निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की जाए।
८६. श्री सचिन पडवल द्वारा मुंबई शहर में महानगरपालिका की अनुदानित शालाओं को प्रदान की जाने वाली बिजली, पानी की सुविधाओं तथा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को आवासीय दरों के अनुसार लिया जाए।
८७. श्री अंकित प्रभु द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभागृह में होने वाली कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब तथा अन्य प्रसार माध्यमों के माध्यम से किया जाए।
८८–८९. श्रीमती यामिनी य. जाधव द्वारा (८८) मुंबई के गिरगांव, दादर, जुहू, वर्सोवा, आक्सा, मार्वे, मढ, गोराई इन सभी प्रमुख समुद्र तटों का निरीक्षण कर यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक शौचालय, वस्त्र परिवर्तन कक्ष, सामान रखने हेतु लॉकर आदि आवश्यक सुविधाएं महानगरपालिका द्वारा सशुल्क उपलब्ध कराई जाएं तथा उनका उचित रखरखाव किया जाए; तथा **(८९)** मुंबई के प्रमुख चौकों एवं ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए महानगरपालिका की स्वामित्व वाली किराए पर उपलब्ध खरीद केंद्र, खानपान केंद्र, शौचालय, निर्धारित अंतराल पर बैठने की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, उत्तम प्रकाश व्यवस्था तथा उद्यान क्षेत्र, प्रकृति एवं संस्कृति के संतुलन के साथ कलात्मक रूप से विकसित लैंडस्केप गार्डन जैसी सुविधाओं से युक्त तथा वाहनमुक्त, सुंदर, शांत एवं आरामदायक 'पैदल यात्री अनुकूल क्षेत्र' विकसित किए जाएं।
९०. श्रीमती मेहर मो. हैदर द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के प्रमुख अस्पतालों तथा १६ परिमंडलीय अस्पतालों में स्वीकृत कुल शय्याओं में से ३० प्रतिशत शय्याएं इन अस्पतालों के अतिदक्षता विभाग, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग तथा बालरोग अतिदक्षता विभाग हेतु आरक्षित रखी जाएं तथा इसके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, अत्याधुनिक उपकरण, ऑक्सीजन व्यवस्था तथा डॉक्टरों एवं नर्सों सहित आवश्यक मानव संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।
९१. श्री. ताजिंदरसिंह तिवाना द्वारा मुंबई शहर में जिस प्रकार गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र किया जाता है, उसी तर्ज पर ई-कचरे का स्रोत पर ही वर्गीकरण अनिवार्य किया जाए तथा महानगरपालिका द्वारा स्वतंत्र निधि, कार्यप्रणाली और प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त कर मुंबई शहर के संपूर्ण ई-कचरे का प्रबंधन स्वयं किया जाए।
९२. श्रीमती हर्षिता अ. नार्वेकर द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों, महामार्गों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए 'वैक्यूम स्वीपिंग मशीन' युक्त वाहनों का उपयोग किया जाए।
९३. श्रीमती सायली र. कुलकर्णी द्वारा शालेय पाठ्यक्रम में कक्षा पाँचवीं से 'मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता' विषय पर एक स्वतंत्र पाठ शामिल किया जाए।
९४. श्री. प्रकाश गंगाधरे द्वारा बृहन्मुंबई के लिए एक स्वतंत्र पार्किंग प्राधिकरण स्थापित कर प्रत्येक प्रभाग का अलग पार्किंग आराखड़ा तैयार किया जाए तथा इसके माध्यम से 'मुंबई पार्किंग ऐप' विकसित कर नागरिकों को रियल टाइम पार्किंग स्लॉट की जानकारी देकर वहाँ वाहन खड़ा करने हेतु ऑनलाइन आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
९५. डॉ. नील सोमैया द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया का नियमित लेखा परीक्षण किया जाए।
९६. श्री. अंकित प्रभु द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा प्रदान करने हेतु 'एयर फिल्टर' लगाए जाएं।
९७. श्रीमती संगीता ज्ञा. शर्मा द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के क्षेत्र में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के अंतर्गत विकसित इमारतों को अधिभोग प्रमाणपत्र देते समय सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए महानगरपालिका के संबंधित विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्रों के साथ-साथ संबंधित विभागीय कार्यालय का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना विकासक के लिए अनिवार्य किया जाए।
९८. श्री. ताजिंदरसिंह तिवाना द्वारा मुंबई शहर के सड़क और चौकों के नामफलक पर जिस व्यक्ति के नाम पर नामकरण किया गया है, उस व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय, उनके कार्य का इतिहास, उपलब्ध छायाचित्र तथा दृश्य-श्रव्य रूप में जानकारी आदि को विभिन्न भाषाओं में 'क्यूआर कोड' के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए।
९९. श्री. मिलिंद शिंदे द्वारा मुंबई की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा कला और खेल क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका में एक स्वतंत्र सांस्कृतिक विभाग स्थापित किया जाए।
१००. श्रीमती लीना पटेल देहेरकर द्वारा महाराष्ट्र राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपमुख्यमंत्री की तस्वीरें राज्य के सभी शासकीय
कार्यालयों, अर्ध-शासकीय संस्थाओं और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभी कार्यालयों में लगाई जाएं।
१०१. श्रीमती सारिका श. झोरे द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के क्षेत्र में सड़कों का सीमेंट कंक्रीटीकरण, मरम्मत, चौड़ीकरण आदि विकास कार्य पूर्ण होने के बाद, उन सड़कों पर लगाए गए महापुरुषों के नामों के फलक सम्मानपूर्वक उसी स्थान पर पुनः लगाए जाएं, ऐसी शर्त सड़क निर्माण आदि विकास कार्यों के ठेकों में शामिल की जाए और संबंधित विभागीय कार्यालयों के अधिकारियों पर इसके पालन की जिम्मेदारी तय की जाए।
१०२. श्रीमती सोनम म. जामसुतकर द्वारा भूखंडों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाओं वाले भूखंडों पर समाज कल्याण केंद्र, मनोरंजन केंद्र, बहुउद्देशीय इमारतों आदि के लिए एक मार्गदर्शक नीति तैयार की जाए तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आरक्षित एवं उसके कब्जे में आई ऐसी इमारतों के नामकरण के संबंध में ठोस नीति बनाई जाए।
१०३–१०५. श्री. प्रभाकर शिंदे द्वारा (१०३) नौकरी, व्यवसाय आदि कारणों से रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियों में गर्भवती महिलाओं हेतु एक अलग डिब्बा आरक्षित किया जाए; **(१०४)** बृहन्मुंबई की स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 'एनसीसी' की कक्षाएं अनिवार्य की जाएं; और **(१०५)** बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा मुंबई शहर को जल आपूर्ति करने वाले बांध क्षेत्रों में जमा गाद को वर्षा ऋतु से पहले कम से कम ५ से १० वर्षों में एक बार हटाया जाए।
१०६. श्री. दीपक कोतेकर द्वारा मुंबई शहर के मैदानों, उद्यानों में तथा 'बेस्ट' उपक्रम के बस डिपो के तहखानों और जमीन के ऊपर आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग सुविधाएं बनाई जाएं।
१०७. श्रीमती श्रद्धा श्री. जाधव द्वारा लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभागार की कार्यवाही का सीधा प्रसारण तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाए।
१०८. श्रीमती किशोरी कि. पेडणेकर द्वारा 'मराठी भाषा' विषय अनिवार्य होने वाली सभी स्कूलों, निजी अनुदानित स्कूलों में 'मनाचे श्लोक' पाठ के लिए प्रतिदिन एक कक्षा अनिवार्य की जाए।
१०९. श्रीमती शितल सु. गंभीर द्वारा उद्यान, स्कूल, अस्पताल जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित बृहन्मुंबई महानगरपालिका के स्वामित्व वाले तथा अन्य प्राधिकरणों को हस्तांतरित भूखंड यदि विकसित नहीं हुए हैं और खाली पड़े हैं, तो उनका हस्तांतरण रद्द कर उन्हें तुरंत महानगरपालिका के कब्जे में लिया जाए तथा उन भूखंडों पर आरक्षण का विकास महानगरपालिका द्वारा स्वयं किया जाए।
११०–१११. श्री. मो. जमीर कुरेशी द्वारा – (११०) मुंबई शहर के प्रमुख सड़कों, उड्डाणपुलों और व्यस्त चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात जाम, मरम्मत के लिए सड़क बंद होना, वर्षा के कारण सड़कों पर पानी जमा होना आदि परिस्थितियों की तथा ऐसे समय में वैकल्पिक मार्ग की सूचना देने के लिए 'डिजिटल सूचना फलक' लगाए जाएं; और **(१११)** संपूर्ण मुंबई शहर में वाहन चालकों को अपने वाहन खड़े करने हेतु 'सेंसर आधारित रियल टाइम पार्किंग सिस्टम' लागू किया जाए।
११२. डॉ. (श्रीमती) सईदा खान द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभी उद्यानों में आवश्यक जल आपूर्ति के लिए कूपनलिकाएं (बोरवेल) खोदी जाएं।
११३. श्री. अजय पाटील द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका में एक स्वतंत्र 'मराठी भाषा विभाग' स्थापित किया जाए।
११४. श्रीमती प्रीति म. सातम द्वारा मुंबई के सभी निर्माण प्रकल्पों, पायाभूत सुविधा प्रकल्पों तथा अन्य गैर-पेय उपयोग के कार्यों के लिए मलजल शोधन संयंत्र के तृतीय स्तर पर शुद्ध किए गए पानी का उपयोग अनिवार्य किया जाए तथा ऐसे सभी कार्यों के लिए पेयजल के उपयोग पर चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाए।
११५. श्रीमती यामिनी य. जाधव द्वारा शहर में कचरा संकलन एवं परिवहन, महानगरपालिका के अस्पतालों की सफाई एवं स्वच्छता, महानगरपालिका की स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना आदि जैसी विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने हेतु मुंबई महानगरपालिका द्वारा बाहरी संस्थाओं को दिए जाने वाले ठेकों में से २५% ठेके मुंबई के महिला बचत समूहों के लिए आरक्षित किए जाएं।
११६–११७. श्री. भास्कर शेट्टी द्वारा (११६) बृहन्मुंबई महानगरपालिका के कार्यों से संबंधित सभी पत्राचार नगरसेवकों को अद्यतन कंप्यूटर तकनीक का उपयोग कर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएं। **(११७)** बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग और 'बेस्ट' उपक्रम के संयुक्त तत्वावधान में 'बेस्ट' बस स्टॉप पर 'क्यूआर कोड' के माध्यम से डिजिटल शिक्षा एवं पुस्तकालय पहल चलाई जाए।
११८. श्री. शिवकुमार झा द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभी प्रभागों में हाई-स्पीड इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा, डिजिटल पुस्तकालय तथा अध्ययन हेतु अलग कक्ष की व्यवस्था वाली कम से कम एक 'ई-अभ्यासिका' स्थापित की जाए।
११९. श्रीमती अजंता रा. यादव द्वारा बृहन्मुंबई के जिन झोपड़पट्टी क्षेत्रों में सीवरेज (मलनिस्सारण) सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, वहां रहने वाले झोपड़पट्टीवासियों से जल बिल में वसूला जाने वाला सीवरेज कर तत्काल रद्द किया जाए।
१२०. श्री. रोहिदास लोखंडे द्वारा शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जांच और अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सरकारी तथा महानगरपालिका के अस्पतालों में एक 'पुलिस सहायता काउंटर' की व्यवस्था की जाए।
१२१. श्रीमती नसीमा जा. जुनेजा द्वारा बृहन्मुंबई की सीमा में नई विकसित तथा पुनर्विकसित होने वाली इमारतों में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने वाले भवन प्रस्तावों को ही स्वीकृति दी जाए।
१२२. श्री. सचिन पडवळ द्वारा मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर, उद्यानों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्थित पेड़ों के चारों ओर हवा और पानी के प्रवाह को बनाए रखते हुए जालीदार प्रकार के लोहे के सुरक्षात्मक ग्रिल लगाए जाएं।
१२३–१२४. डॉ. नील सोमैया द्वारा (१२३) बृहन्मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों में 'एआई' विषय की प्राथमिक जानकारी देने हेतु पाठ्यक्रम विकसित किया जाए तथा इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक, पाठ्यक्रम संरचना, डिजिटल साधन एवं सहायक उपकरण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं; और **(१२४)** बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा प्रत्येक प्रभाग स्तर पर **२४ x ७** कार्यरत अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्ज आपदा प्रबंधन कक्ष स्थापित किए जाएं।
१२५. श्री. प्रतीक कर्पे द्वारा मुंबई शहर के पूर्व एवं पश्चिम द्रुतगति महामार्गों पर 'पे एंड यूज़' सिद्धांत पर निश्चित दूरी पर महिला, पुरुष एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग एवं सुरक्षित सुविधाओं सहित, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन आदि से युक्त वातानुकूलित शौचालय स्थापित किए जाएं।
१२६. श्रीमती साक्षी दि. दळवी द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका और मेट्रो प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई शहर के मेट्रो मार्ग के खंभों पर मानक डिज़ाइन के सुसज्ज विज्ञापन फलक लगाने के लिए आकार, शुल्क, अनुमति प्रक्रिया, रखरखाव, जिम्मेदारी, सुरक्षा शर्तें तथा अवैध पोस्टरों पर दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शक नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए।
१२७–१२८. श्रीमती जागृति प्र. पाटील द्वारा (१२७) बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा मुंबई के दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एआई, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एमएस-सीआईटी तथा अन्य कंप्यूटर पाठ्यक्रमों की पूरी फीस अधिकृत एवं पंजीकृत प्रशिक्षण केंद्रों को देकर ऐसे विद्यार्थियों को ये पाठ्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किए जाएं; और **(१२८)** बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभी अस्पतालों, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों में ९ से १४ वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए 'ह्यूमन पैपिलोमावायरस' (गार्डासिल) वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
१२९. श्री. अजय पाटील द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा मुंबई शहर के गणेशोत्सव मंडलों के गणपति मूर्तियों को लाने और विसर्जन हेतु उपयोग में आने वाली ट्रॉलियों को रखने के लिए शहर के फ्लाईओवरों के नीचे तथा महानगरपालिका की स्वामित्व वाली खाली जगहों पर स्थान उपलब्ध कराया जाए।
१३०. श्री. अजित रावराणे द्वारा अहमदाबाद, तेलंगाना आदि राज्यों की 'कूल रूफ पॉलिसी' की तर्ज पर मुंबई शहर में नई बनने वाली इमारतों पर सौर परावर्तक पेंट लगाना अनिवार्य करने की शर्त 'आराखड़ा अस्वीकृति सूचना' में शामिल की जाए।
१३१. श्री. यशोधर फणसे द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा कचरा पृथक्करण, वर्मी कंपोस्ट परियोजना, वर्षा जल संचयन एवं उपयोग प्रणाली, सौर ऊर्जा तथा अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाएं लागू करने की इच्छुक मुंबई शहर की आवासीय सोसायटियों को हरित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,00,000 (एक लाख रुपये) का अनुदान दिया जाए।
१३२. श्रीमती आयशा सु. वनू द्वारा लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभागार की संपूर्ण कार्यवाही को आधिकारिक माध्यमों द्वारा लाइव प्रसारित किया जाए तथा साथ ही उस कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए।
१३३. डॉ. (श्रीमती) सईदा खान द्वारा कोंकण क्षेत्र में वर्षा के कारण समुद्र में जाने वाले अतिरिक्त अरबों लीटर पानी को मुंबई की ओर मोड़ने हेतु एक परियोजना शुरू की जाए।
१३४. श्री. प्रकाश मोरे द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मेट्रो प्राधिकरण के साथ समन्वय कर मुंबई शहर की सभी मेट्रो लाइनों के नीचे स्थित डिवाइडरों के चारों ओर कम से कम 10 फीट ऊंचाई की लोहे की जालीदार सुरक्षा बाड़ लगाई जाए।
१३५. श्रीमती आशा सु. मराठे द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूली स्तर पर ही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी हेतु स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए।
१३६–१३७. श्री. रुपेश सावरकर द्वारा (१३६) बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में एक आधुनिक और सुसज्ज 'मराठी कला केंद्र' स्थापित किया जाए; और **(१३७)** मुंबई शहर के प्रमुख सार्वजनिक उद्यानों और खुले मैदानों में 'ओपन एयर थिएटर' (मुक्त रंगमंच) का निर्माण किया जाए।
१३८. श्री. चंदन शर्मा द्वारा मुंबई शहर की वर्षा जल निकासी नालियों के चैंबरों के नीचे जमीन में निश्चित दूरी पर जालीदार आवरण वाली कूपनलिकाएं खोदी जाएं।
१३९. श्रीमती मीनल सं. तुर्डे द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा प्रशिक्षित महिला बचत समूहों की घरेलू कार्य जैसे कामवाली, रसोइया, देखभाल करने वाली आदि सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाओं का डेटा एकत्र कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक 'ऐप' विकसित किया जाए।
१४०. श्री. यशवंत किल्लेदार द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 'एयर मॉनिटरिंग प्रणाली' को सैटेलाइट इंटरनेट से जोड़कर महानगरपालिका की वेबसाइट पर वायु प्रदूषण से संबंधित क्षेत्रवार जानकारी प्रतिदिन प्रकाशित की जाए।
१४१. श्री. सन्नी सानप द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने प्रत्येक प्रभाग में अग्निशमन दल एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मूलभूत प्राथमिक उपचार और बचाव कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक नागरिकों को 'आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक' के रूप में नियुक्त किया जाए तथा उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र प्रदान किए जाएं।
१४२–१४३. श्रीमती आयशा सु. वनु द्वारा (१४२) बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को अधिकृत जल कनेक्शन हेतु अनुदान देने की योजना लागू की जाए; और **(१४३)** मुंबई शहर को जल आपूर्ति करने वाले सभी जलाशयों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कर उनमें जमा गाद को चरणबद्ध एवं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हटाया जाए।
१४४. श्री. मो. जमीर कुरेशी द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा मुंबई शहर में 'स्पंज सिटी' की अवधारणा लागू की जाए।

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दिनांक २२ अप्रैल २०२६

महापौर के आदेशानुसार,
मंजिरी सं. देशपांडे,
महानगरपालिका सचिव

क्र. जसंअ /149 / विज्ञापन /2026-27

सरकारनामा

सब कुछ पॉलिटिकल

DBD दो बजे दोपहर 8

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

मुंबई | गुरुवार 23 अप्रैल 2026

विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग सख्त

एजेंसी । कोलकाता/चेन्नई

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को होने वाले मतदान से ठीक पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ईवीएम (EVM) के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी, चाहे वह इत्र, स्याही या गोंद लगाना ही क्यों न हो, उसे 'चुनावी अपराध' माना जाएगा।

केमिकल और इत्र पर पाबंदी

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मतपत्र इकाई (Ballot Unit) पर किसी भी तरह का इत्र, परफ्यूम, स्याही या अन्य केमिकल लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अक्सर मतों की गोपनीयता भंग करने या वोटिंग प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ऐसी कोशिशें की जाती हैं। अब इसे सीधे EVM से छेड़छाड़/हस्तक्षेप माना जाएगा।

उम्मीदवार बटन का स्पष्ट होना अनिवार्य

पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर बूथ पर यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवारों के नाम और उनके सामने वाले बटन पूरी तरह साफ दिखाई दें। किसी भी बटन को टेप, गोंद या कागज से ढका नहीं होना चाहिए।

ईवीएम से छेड़छाड़ होने पर पुनर्मतदान का आदेश, गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई तय

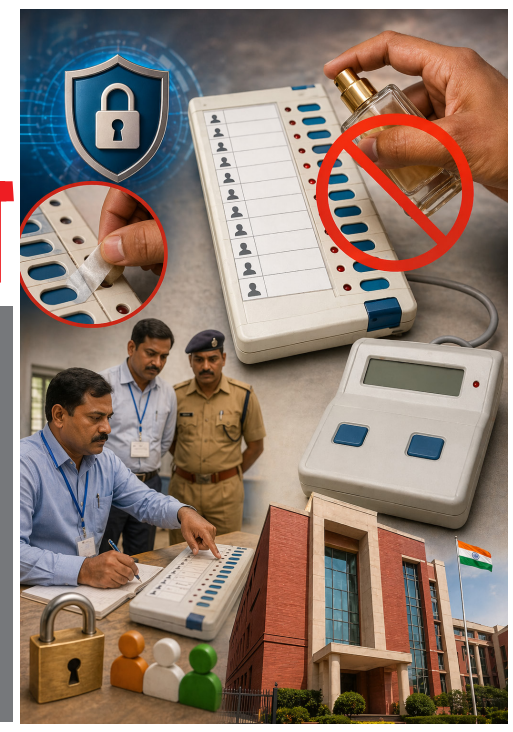

पीठासीन अधिकारियों की बढ़ी जिम्मेदारी

अगर किसी पोलिंग बूथ पर EVM के साथ किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी तुरंत सक्रिय हो जाती है। उन्हें बिना किसी देरी के सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। समय पर कार्रवाई न करने या लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधित अधिकारी भी जवाबदेही से बच नहीं सकते। ऐसे मामलों में अधिकारियों पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे उनकी सेवा पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हर अधिकारी को सतर्कता और पारदर्शिता के साथ अपनी ड्यूटी निभाना बेहद जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दोबारा मतदान की चेतावनी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी मतदान केंद्र पर EVM के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि होती है, तो वहां पुनर्मतदान (Re-polling) कराने में किसी भी प्रकार की ढील या संकोच नहीं बरता जाएगा। आयोग का मानना है कि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में न केवल संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराया जाएगा, बल्कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज होना और अन्य कानूनी दंड शामिल हो सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश न करे।

बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस : शाह

एजेंसी । कोलकाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है और राज्य में उसका कोई जनाधार नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेजी से मजबूत हो रही है और आने वाले चुनावों में बड़ा प्रदर्शन करेगी। रैली के दौरान शाह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि वे केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा विकास और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव का समय आ गया है और जनता भाजपा के साथ खड़ी है।

प.बंगाल सरकार पर साधा निशाना

रैली में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और राज्य को गुंडों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या राज्य में चार शादियों की छूट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, जिससे तीन तलाक और बहु-विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इसका समाधान कमल को वोट देने से मिलेगा। इसके साथ ही शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह कर रही हैं।

केजरीवाल ने ममता बनर्जी से फोन पर की बात, दिया समर्थन

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी देश के लोकतंत्र की सबसे कठिन और अहम लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर बात की और उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, अभी ममता दीदी से फोन पर बात हुई। उन्हें पूरा समर्थन और एकजुटता जताई। वह बेहद कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी जी सभी संस्थाओं, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद वह हारेंगे।

आई-पीएसी छापेमारी विवाद

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आचरण ने लोकतंत्र को खतरे में डाला: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच चल रहे कानूनी विवाद में बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने स्पष्ट कहा कि यदि एक मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो इसे केवल 'केंद्र बनाम राज्य' का राजनीतिक विवाद कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार, यह सीधे तौर पर कानून के शासन (Rule of Law) और संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा आचरण लोकतंत्र को खतरे में डालता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा पूरी संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है।

जांच की स्वतंत्रता और 'मूकदर्शक' अधिकारी

यह मामला जनवरी 2026 में कोयला घोटाले की जांच के दौरान I-PAC के कार्यालय और उसके निदेशक के आवास पर हुई छापेमारी से जुड़ा है। ED का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने खुद वहां पहुंचकर अधिकारियों को धमकाया और डिजिटल साक्ष्य (लैपटॉप और फोन) कब्जे में ले लिए। इस पर जस्टिस मिश्र ने राज्य सरकार के वकील से तीखा सवाल पूछा, रक्या जांच अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि जब मुख्यमंत्री खुद छापेमारी वाली जगह पर घुस आएं, तो वे मूकदर्शक बनकर खड़े रहें?ः अदालत ने जोर दिया कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सक्रिय तलाशी अभियान में दखल देता है, तो यह जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और उनकी वैधानिक ड्यूटी पर गंभीर प्रहार है।

ब्रीफ खबर

गृह मंत्रालय को मिली पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित प्रणाली

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा एजेंसियों को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एआई से लैस आधुनिक सैटेलाइट सिस्टम प्रज्ञा को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। इसके जरिये निगरानी, विश्लेषण और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। कर्तव्य भवन-3 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत ने यह प्रणाली केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि प्रज्ञा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे देश में ही विकसित किया गया है। यह आधुनिक इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम डीआरडीओ की प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की ओर से तैयार किया गया है। इसकी सबसे अहम विशेषता यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली है, जो वास्तविक समय में डाटा विश्लेषण कर सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है।

आरोग्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निधि का सही नियोजन करें : राज्यमंत्री

मुंबई। मेघना साकोरे-बोर्डीकर ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निधि का उचित और प्रभावी नियोजन करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य बजट तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत प्राप्त निधि के उपयोग और नियोजन को लेकर आरोग्य भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही जिलास्तर पर थैलेसीमिया मरीजों को नियमित रूप से दिव्यांग प्रमाणपत्र देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में महाराष्ट्र राज्य औषधि द्रव्य एवं सामग्री खरीद प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा की गई। वर्ष 2024 से 2026 के बीच खरीदी गई दवाओं और उपकरणों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा चालू वर्ष की कार्ययोजना और रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में PCOD क्लिनिक शुरू करने पर भी विचार किया गया। इसे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया।

उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में लू का तांडव शुरू

एजेंसी । नई दिल्ली

भारत के एक बड़े हिस्से में चिलचिलाती गर्मी और लू ने दस्तक दे दी है। इससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। सूरज के कड़े तेवर और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम विभाग ने जारी किया भीषण गर्मी का अलर्ट

इन इलाकों में कब तक रहेगा लू का असर?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के छिटपुट इलाकों में 24 और 25 अप्रैल को भीषण लू चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा सकता है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी महसूस होगी। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन दो दिनों में विशेष सावधानी बरतें। इन राज्यों में गर्म हवाओं का असर दिन के साथ-साथ देर शाम तक बने रहने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से राहत मिलना मुश्किल होगा।

उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक गर्मी का क्या हाल?

उत्तर प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप चरम पर रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 25 अप्रैल तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 26 अप्रैल के बीच लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजस्थान में 24 से 26 अप्रैल और मध्य प्रदेश में 23 से 26 अप्रैल तक लू चलने की आशंका है। इसके अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ के इलाकों में 24 से 27 अप्रैल के दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भी 22 और 23 अप्रैल को लू का कहर देखने को मिलेगा।

इन राज्यों में गर्म रातें परेशान करेंगी?

केवल लू ही नहीं, बल्कि उमस भरी गर्मी भी कई तटीय और दक्षिण भारतीय राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में 22 से 25 अप्रैल के बीच भारी उमस रहने वाली है। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा जैसे कुछ हिस्सों में रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।

बंगाल में मौसम का क्या हाल?

दक्षिण बंगाल के जिले भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की चपेट में हैं, वहीं उत्तर बंगाल के इलाकों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को ताजा बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में 25 अप्रैल तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। सूखी पछुआ हवाओं और तेज धूप के कारण तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है।

मणिपुर में फिर तनाव

हिंसा के विरोध में विभिन्न संगठनों ने बुलाया बंद

12 जिलों में दिखा असर

एजेंसी । इंफाल

मणिपुर में जातीय हिंसा की तपिश और विभिन्न समुदायों के बीच पनपा आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बुधवार को राज्य के अलग-अलग जातीय संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद के कारण मणिपुर के कुल 16 में से 12 जिलों में सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी में बीते सात अप्रैल को हुए बम हमले के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) ने पांच दिवसीय बंद का आह्वान किया है। इस हमले में दो मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस बंद का इंफाल घाटी के सभी पांच जिलों में व्यापक असर देखा जा रहा है। इंफाल पश्चिम के सगोलबंद और पटसोई जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। यातायात पूरी तरह ठप होने से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं।

नागा बहुल इलाकों में तीन दिनों का पूर्ण बंद

घाटी के साथ-साथ राज्य के पहाड़ी जिलों में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यूनाइटेड नागा काउंसिल की ओर से बुलाए गए तीन दिवसीय बंद का आज दूसरा दिन था। यह बंद 18 अप्रैल को उखरुल जिले में दो तंगखुल नागा व्यक्तियों की हत्या के विरोध में बुलाया गया है। नागा बहुल छह पहाड़ी जिलों में इस बंद का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है।

केसीआर पर फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई

कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामला

एजेंसी । हैदराबाद

हैदराबाद में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और तीन अन्य को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आयोग कालेश्वरम परियोजना में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए गठित किया गया था। केसीआर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया था। उनका कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने और जिरह का मौका नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट का अहम आदेश

मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि आयोग का गठन अवैध या असंवैधानिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि जिन निष्कर्षों से याचिकाकर्ताओं की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है और जो बिना उचित प्रक्रिया के दिए गए हैं, वे अमान्य होंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। रिपोर्ट में केसीआर के अलावा तत्कालीन सिंचाई मंत्री और अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। बाद में यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई और इसे सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया।

नेपाल के गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

काठमांडू। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह फैसला अपने वित्तीय निवेशों (शेयरों) को लेकर उठे सवालों के बीच नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लिया, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। फेसबुक पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए गुरुंग ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिक मानकों को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता का भरोसा किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

गुरुंग ने अपने पोस्ट में स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से उनकी संपत्ति और शेयरों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की चिंताओं को उन्होंने गंभीरता से लिया और इसी वजह से पद छोड़ना उचित समझा। उन्होंने 'जेन जेड' आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के युवा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। गुरुंग ने कहा कि नेतृत्व को हमेशा जवाबदेह रहना चाहिए और नैतिकता ही सही रास्ता दिखाती है।

समंदर में फंसे जहाजों को ठग रहे साइबर अपराधी

ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर शिपिंग कंपनियों को लूट रहे

दुबई/एथेंस। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे व्यापारिक पोतों पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा मिसाइलों या समुद्री लुटेरों का नहीं बल्कि साइबर ठगों का है। यूनानी समुद्री जोखिम फर्म मार्क्स ने एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर शिपिंग कंपनियों को लूट रहे हैं। ये ठग फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले बिटकॉइन और टीथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी में पारागमन शुल्क (ट्रांजिट फीस) की मांग कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है, जो वर्तमान में युद्ध की वजह से बंद पड़ा है।

ठगी का तरीका

कंपनियों को ईमेल भेजकर कहा जाता है कि वे अपने जहाज के दस्तावेज ईरानी सुरक्षा सेवाओं को समीक्षा के लिए सौंपें। दस्तावेज मिलने के बाद ठग एक ट्रांजिट फीस तय करते हैं। इसके बदले वे सुरक्षित मार्ग का संदेश भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है- फीस मिलने के बाद ही आपका जहाज बिना किसी बाधा के तय समय पर जलडमरूमध्य को पार कर सकेगा। एक जहाज ने झांसे में आकर इन ठगों को भुगतान भी कर दिया था। 18 अप्रैल को जब ईरान ने जांच के लिए होर्मुज का मार्ग खोला तो जिन जहाजों ने इन फर्जी निर्देशों का पालन किया था।